लखनऊ

शुक्रवार, 3 जुलाई, 2026

वर्ष : 11 । अंक: 306

मूल्य : 1 रुपये

पृष्ठ : 8

UPHIN/2014/57034

हिंदी दैनिक

आर्यावर्त क्रांति

जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है।

TODAY WEATHER

DAY 41° Hi

NIGHT 29° Low

संक्षेप

बेंगलुरु में दर्दनाक हादसा : पत्थर की खदान में 40 फीट ऊंची चट्टान गिरी, 7 मजदूरों की गई जान-कई घायल

बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु साउथ तालुक के मादापट्टना इलाके स्थित एक पत्थर की खदान में अचानक विशालकाय चट्टान ढहने से बिहार के 7 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य मजदूर घायल हो गए। पुलिस के अनुसार, हादसा उस समय हुआ जब मजदूर खदान में पत्थर तोड़ने और खुदाई का काम कर रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, साइट पर करीब 18 मजदूर मौजूद थे। इसी दौरान लगभग 40 फीट की ऊंचाई से एक भारी-भरकम चट्टान अचानक मजदूरों पर आ गिरी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। मृतक सभी दिहाड़ी मजदूर थे और स्टोन क्रशर साइट पर काम करते थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गए। मलबा हटाने का अभियान तुरंत शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रशासन अभी घायलों की संख्या और मलबे में अन्य मजदूरों के फंसे होने की आशंका की जांच कर रहा है। हादसे के बाद प्रशासन ने पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। राहत दल यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि मलबे के नीचे कोई अन्य व्यक्ति न फंसा हो। पुलिस ने पुष्टि की है कि हादसे में जान गंवाने वाले सभी सात मजदूर बिहार के रहने वाले थे। उनके परिजनों को घटना की सूचना दी जा रही है। वहीं, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा किन कारणों से हुआ और क्या खदान में सुरक्षा मानकों की अनदेखी या किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी।

भाजपा प्रवक्ता ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। ऊधम सिंह नगर में किच्छा में एक फार्म है जिसको लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल वहां स्थित 4 एकड़ के खान फार्म को लेकर आज भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस PC में उन्होंने वाड्रा परिवार और विशेषतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के एक विधायक कुछ लोगों के साथ उस फार्म पर गए और वहां रह रही बुजुर्ग महिला को फार्म खाली करने के लिए धमकाया है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि PC में प्रदीप भंडारी ने क्या कुछ कहा। PC में बात करते हुए भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोप लगाते हुए कहा, 'सायरा वाड्रा जो प्रियंका वाड्रा की जेठानी हैं, वो इस (खान फार्म) जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। जब यह लैंड एक सिबिल डिस्प्यूट है और यह बात गांधी-वाड्रा परिवार को समझ आ गया है कि कानूनी तौर पर इस 4 एकड़ की जमीन पर सायरा वाड्रा कब्जा नहीं कर सकती हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के किच्छा विधायक और प्रियंका वाड्रा के करीबी तिलक राज बेहड़ कल देर रात को 100 लोगों के साथ उस जमीन पर जाते हैं और वहां जो 90 वर्षीय महिला है, उन्हें धमकाते हैं कि अगर उन्होंने यह जमीन खाली नहीं की तो उन्हें जान से मार दिया जाएगा। यह आरोप खुद उस महिला यानी नसरीन खान ने लगाया है।'

जापानी पीएम ताकाइची को पीएम मोदी ने बताया छोटी बहन, भारत-जापान के बीच किन-किन मसलों पर हुई डील

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत और जापान के रिश्ते हमेशा भरोसे, सम्मान और रणनीतिक साझेदारी के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन गुरुवार को नई दिल्ली में 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान यह रिश्ता उस वक्त और खास बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची को अपनी 'छोटी बहन' बताया। यह सिर्फ एक आत्मीय संबोधन नहीं था बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते विश्वास और मजबूत होते रिश्तों का प्रतीक भी माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों, इंडो-पैसिफिक में बढ़ते तनाव और चीन की बढ़ती आक्रामकता के बीच भारत और जापान ने साफ संकेत दिया कि उनकी साझेदारी अब केवल आर्थिक सहयोग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे अहम क्षेत्रों में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी।

शिखर वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े फैसलों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सनाए ताकाइची की भारत यात्रा दोनों देशों के संबंधों में नया अध्याय लिख रही है। उन्होंने ताकाइची को 'जापान फर्स्ट प्रधानमंत्री' और दूरदर्शी नेता बताते हुए कहा कि भारत और जापान मुक्त, खुला और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के साझा विजन पर काम कर रहे हैं। इस दौरान रक्षा, निवेश, तकनीक, ऊर्जा सुरक्षा, सप्लाई चेन और हरित ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में कई अहम समझौतों पर सहमति बनी।

भारत-जापान रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाले बड़े फैसले

16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते एक साल में भारत और जापान के बीच 120 नए कारोबारी समझौते हुए हैं। अब दोनों देशों का लक्ष्य अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन येन के जापानी निवेश को आकर्षित करना है। यह निवेश विनिर्माण, बुनियादी ढांचे, आधुनिक तकनीक और औद्योगिक विकास को नई गति देगा।

रक्षा सहयोग भी इस सम्मेलन का सबसे बड़ा आकर्षण रहा। भारत और जापान ने अपने पहले रक्षा सह-विकास प्रोजेक्ट पर साइन किए। इसके तहत दोनों देश संयुक्त रूप से रक्षा तकनीकों का विकास करेंगे। सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय शांति, समुद्री सुरक्षा और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए इस समझौते को बेहद अहम माना जा रहा है।

आर्थिक सुरक्षा और सप्लाई चेन पर बनी नई रणनीति

दोनों नेताओं ने वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए आर्थिक सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा पर साझा रोडमैप तैयार करने का भी ऐलान किया। इस योजना के तहत सेमीकंडक्टर, क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्रिटिकल मिनरल्स और उभरती तकनीकों में सहयोग बढ़ाया जाएगा। साथ ही दोनों देशों ने मजबूत और भरोसेमंद सप्लाई चेन तैयार करने पर भी सहमति जताई, ताकि वैश्विक संकटों के दौरान उद्योगों पर असर कम पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने 'गोवर्धन पहल' के तहत भारत-जापान बायोगैस इनिशिएटिव की शुरुआत का भी ऐलान किया। इस पहल के जरिए देशभर में आधुनिक बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे।

इंडो-पैसिफिक पर साझा रणनीति

दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि वे मुक्त, खुले और नियम-आधारित इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के पक्षधर हैं। समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान को लेकर दोनों नेताओं ने साझा प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अभ्यास, समुद्री सहयोग और आधुनिक तकनीकों में साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

3 दिन के भारत दौरे पर हैं ताकाइची

जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची 1 से 3 जुलाई तक भारत की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वह 16वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगी। इस सम्मेलन में दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

बम-बम भोले के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रा शुरू, पहला जत्था रवाना

श्रीनगर। पवित्र अमरनाथ यात्रा 2026 का शुभारंभ गुरुवार को 'बम-बम भोले' के गगनभेदी जयकारों के बीच हो गया। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से सुबह 4 बजे श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा के लिए रवाना किया।

57 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 3 जुलाई से पहलगाम और बालटाल, दोनों मार्गों से संचालित होगी और 28 अगस्त (रक्षाबंधन) को संपन्न होगी।पहले जत्थे में केवल उन्हीं श्रद्धालुओं को शामिल किया गया, जिन्होंने पहले से पंजीकरण कराया था, कार्ड प्राप्त किया था और ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की थी। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक करीब चार लाख श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, चिकित्सा, परिवहन, आवास, संचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं पहले ही पूरी कर ली हैं, ताकि यात्रा सुरक्षित और सुचारु रूप से संपन्न हो सके। यात्रा शुरू होने से एक दिन पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को बेस कैंप का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं, ठहरने की व्यवस्था, बिजली-पानी की उपलब्धता, हेल्प डेस्क और अन्य इंतजामों का विस्तृत जायजा लिया तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उधर, देश की अन्य प्रमुख धार्मिक यात्राओं में भी श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बना हुआ है। चारधाम यात्रा में 1 जुलाई तक बद्रीनाथ धाम में 14.5 लाख और केदारनाथ धाम में 13.75 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण व जहाजों से शुल्क वसूली चाहता है ईरान, इसके लिए बल प्रयोग को भी तैयार

दोहा/दुबई। अमेरिका और ईरान के बीच बुधवार को दोहा (कतर) में हुई तकनीकी बातचीत में होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों की आवाजाही पर सहमति और युद्धविराम सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। चर्चा की सीधी जानकारी रखने वाले सूत्र ने बताया कि ईरान होर्मुज पर पूर्ण नियंत्रण और खाड़ी में आने-जाने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की क्षमता के लिए अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाने के लिए दृढ़ है, भले ही इसके लिए बल प्रयोग करना पड़े। ईरानी अधिकारी ने भी यही जानकारी दी। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर और दूत स्टीव विटकॉफ ने कतर के पीएम से मुलाकात की। यह वार्ता गत माह हस्ताक्षरित 14-सूत्रीय अंतरिम समझौते पर आधारित है, जिसमें युद्ध रोकना, होर्मुज को फिर खोलना और 60 दिन के स्थायी शांति समझौते के लिए वार्ता शुरू करना शामिल था।

बहराइच में ड्रग्स नेटवर्क पर बड़ा प्रहार : अवैध गोदाम से कोडीनयुक्त कफ सिरप की 8,000 शीशियां बरामद

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

बहराइच। बहराइच जिले में औषधि विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने एक दवा कारोबारी के अवैध गोदाम पर छापेमारी करकोडीनयुक्त कफ सिरप की 8,000 से अधिक शीशियां बरामद की हैं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। जिला औषधि निरीक्षक विनय कृष्ण ने बृहस्पतिवार को बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर बुधवार को औषधि विभाग, थाना दरगाह शरीफ और थाना रूपईडीहा पुलिस की संयुक्त टीम ने दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र के परसौरा गांव में दवा कारोबारी अजय कुमार यादव के एक अवैध गोदाम पर छापेमारी की। उन्होंने बताया कि छापेमारी के दौरान गोदाम से पेटियों

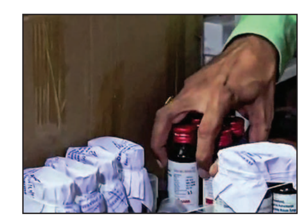

में भरकर रखी गईं कोडीनयुक्त कफ सिरप की 8,000 से अधिक शीशियां बरामद हुईं। बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8/21 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कृष्ण ने बताया कि अजय कुमार यादव के पास दूसरे पते पर दवा विक्रय का लाइसेंस था, लेकिन जिस गोदाम में कफ सिरप का भंडारण किया गया था, उसके लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था। बहराइच में कफ सिरप की तस्करी का यह कोई पहला मामला नहीं है।

भाजपा के 10 टुकड़े होंगे, शिंदे भी नहीं बचेगा... संजय राउत ने दी धमकी

मुंबई, एजेंसी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बार फिर बीजेपी के खिलाफ जहर उगला। गुरुवार को भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए राउत ने बीजेपी के 10 टुकडे. होने की धमकी दी। राउत ने आरोप लगाया कि भाजपा की पूरी नेतृत्व टीम विपक्षी पार्टियों को तोड़ने और बगावत कराने की आदी हो चुकी है। भाजपा को दलों को तोड़ने का ऐसा चस्का लग गया है कि वह किसी को भी नहीं बख्शेगी।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राउत ने कहा, " भाजपा वालों पर पार्टियां तोड़ने की धुन इस कदर सवार है जैसे वे नशे में हों। वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। आखिर में एक-दूसरे की पार्टियां भी तोड़ डालेंगे।" उन्होंने आगे चेतावनी देते हुए कहा, "मैं पहले भी कह चुका हूं कि जिस दिन वे सत्ता से बाहर होंगे और केंद्रीय एजेंसियां हमारे नियंत्रण में आ जाएंगी, उस दिन भाजपा 10 टुकड़ों में बंट जाएगी और वह भी सिर्फ 10 मिनट में।" राउत की यह टिप्पणी हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आई है। बुधवार को ही शिवसेना (UBT) के एमएलसी सचिन अहीर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए हैं। उसके ठीक बाद राउत ने उन पर भी निशाना साधा। राउत ने अहीर पर "लालच" का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें पार्टी ने सब कुछ दिया था, फिर भी वे वफादारी भूल गए। राउत ने कहा, "सचिन अहीर को एमएलसी बनाया गया, पार्टी का डिप्टी लीडर बनाया गया, कामगार सेना का वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया।

यूपी पुलिस में रिकार्डतोड़ तबादले, 125 डिप्टी एसपी इधर से उधर

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पुलिस में रिकॉर्डतोड़ फेरबदल किए गए हैं। गुरुवार को एक साथ 125 डिप्टी एसपी अधिकारियों को इधर-उधर किया गया है। इनमें वो सभी अधिकारी शामिल हैं, निरीक्षक से डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोशन दिया गया है।

जारी तबादला सूची के अनुसार विभिन्न जनपदों, पुलिस कमिश्नरेट, पीएसी, एटीएस, रेलवे पुलिस तथा अन्य इकाइयों में तैनात अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस व्यापक तबादले का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना और प्रशासनिक कार्यों में गति लाना बताया जा रहा है। शासन के आदेश के बाद सभी स्थानांतरित अधिकारियों को शीघ्र

नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी सूची के अनुसार, कमलेश कांत का तबादला मुरादाबाद से गौतमबुद्ध नगर कमिश्नरेट किया गया है, जबकि सुनील कुमार सिंह को भदोही से बिजनौर भेजा गया है। अरुण कुमार शुक्ला को गोंडा से कौशांबी, मुकेश कुमार त्यागी को सहारनपुर से 47वीं वाहिनी पीएसी गाजियाबाद तथा जावेद इकबाल खान को खीरी से 48वीं वाहिनी पीएसी सोनभद्र में नई तैनाती दी गई है। इसी क्रम में रणवीर सिंह यादव को बागपत से शाहजहांपुर, राम किशन को बाराबंकी से गाजियाबाद कमिश्नरेट, अमित प्रताप सिंह को एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ से बहराइच तथा शिव ठाकुर को सहारनपुर से मेरठ भेजा गया है। वहीं संदीप कुमार वर्मा, प्रदीप कुमार शर्मा, संदीप कुमार राय, विकास प्रताप सिंह चौहान, विजय कुमार पांडेय, रंजना सचान, संजय कुमार सिंह, अजय पाल सिंह, मुकेश कुमार, विवेक कुमार तिवारी, भास्कर कुमार तथा कई अन्य अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तबादला सूची में मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर नगर, आगरा, झांसी, बरेली, अयोध्या, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, रायबरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बिजनौर, बागपत, बलरामपुर, बहराइच, बुलंदशहर सहित अनेक जिलों के अधिकारी शामिल हैं। शासन का कहना है कि इस व्यापक प्रशासनिक फेरबदल का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाना तथा पुलिस व्यवस्था को मजबूत करना है।

वाराणसी की सुरक्षा एजेंसी से जुड़े तार, हाउसकीपिंग स्टाफ से कराई जा रही थी नोटों की गिनती

आर्यावर्त क्रांति

अयोध्या। अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर में चढ़ावे और दान की कथित चोरी के मामले में चल रही जांच में एक बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ आया है। जांचकर्ताओं को इस पूरे मामले का एक 'वाराणसी कनेक्शन' मिला है। इस खुलासे के बाद अब जांच का दायरा केवल एक मामूली चोरी तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जांच एजेंसियां अब मंदिर के दान प्रबंधन, आउटसोर्सिंग सिस्टम, बैंकिंग प्रक्रियाओं और सुरक्षा कर्मियों की भर्ती में हुई गंभीर चूक की गहराई से पड़ताल कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए आठ आरोपियों में से छह वाराणसी स्थित एक निजी सुरक्षा फर्म, सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

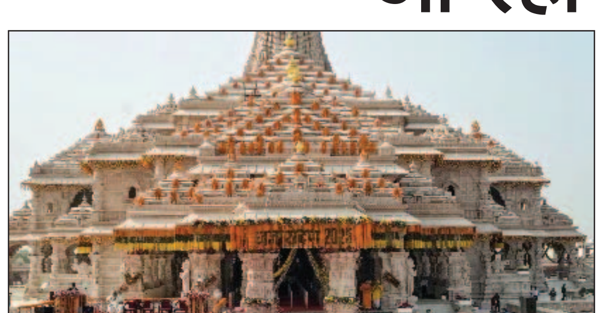

के पेरोल पर थे।

सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने अयोध्या में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की न्यू घाट शाखा को कर्मचारी उपलब्ध कराए थे। बैंक ने कथित तौर पर कैश गिनने के काम में मदद के लिए 19 कर्मचारियों की मांग की थी। वाराणसी स्थित एजेंसी ने कर्मचारियों की भर्ती की और उन्हें SBI में तैनात किया, जिसके बाद उन्हें राम मंदिर में प्राप्त दान को गिनने और संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। जांचकर्ताओं को संदेह है कि ये कर्मचारी कथित तौर पर दो मुख्य आरोपियों, अनिल मिश्रा और टिन्नू यादव के करीबी सहयोगी थे। जांच के अनुसार, एजेंसी ने भर्ती किए गए सभी 19 कर्मचारियों को तैनाती के लिए SBI टीम को सौंप दिया। बाद में इन कर्मचारियों को दान गिनने और मंदिर के कैश कलेक्शन को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। कथित तौर पर प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 20,000 रुपये का मासिक वेतन दिया जाता था। हालांकि, जांच से पता चला है कि इन कर्मचारियों को मूल रूप से हाउसकीपिंग के काम के लिए भर्ती किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें दान के कैश को गिनने और प्रबंधित करने की अत्यंत संवेदनशील जिम्मेदारी सौंप दी गई।

भर्ती प्रक्रिया और आउटसोर्सिंग सिस्टम जांच के दायरे में

सूत्रों ने बताया कि राम मंदिर का दैनिक दान और चढ़ावा अयोध्या में SBI की तुलसी नगर शाखा में जमा किया जाता था। बैंक ने कैश को गिनने, छांटने और सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराने के लिए वाराणसी स्थित आउटसोर्सिंग एजेंसी को काम पर रखा था। जांचकर्ता अब यह जांच कर रहे हैं कि क्या भर्ती प्रक्रिया में उचित पारदर्शिता बरती गई थी और क्या आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों को सौंपी गई जिम्मेदारियां उचित थीं। सूत्रों का यह भी दावा है कि कुछ नियुक्तियां पारदर्शी चयन प्रक्रिया के बजाय सिफारिशों के आधार पर की गई हो सकती हैं।

सुरक्षा एजेंसी ने विवाद से खुद को अलग किया

सैनिक सिक्योरिटी सर्विसेज के मालिक गौरव सिंह ने अपनी कंपनी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के बीच किसी भी सीधे संबंध से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कंपनी का समझौता केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ था।

आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, ट्रस्ट में बढ़ी अंदरूनी कलह

अयोध्या। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भीतर भी आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। पहली बार ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर खुलकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की जिम्मेदारी गोपाल राव की है और वे राजनीति कर रहे हैं। महंत दिनेंद्र दास ने कहा, पूरी गलती गोपाल राव की है। वे सभी को उलझा देते हैं और राम की परंपरा को नहीं मानते। गोपाल राव राम मंदिर निर्माण के प्रभारी और ट्रस्ट के आमंत्रित सदस्य रहे हैं। वे मूल रूप से कर्नाटक के निवासी हैं। उधर, सूत्रों के अनुसार चढ़ावा चोरी के आरोपियों के खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। अयोध्या विकास प्राधिकरण (रष्ढ्र) ने उन मकानों की पहचान कर ली है, जिनका निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के हुआ है या जिनमें नियमों का उल्लंघन किया गया है। ऐसे मकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी चल रही है।

प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटला, मुख्यमंत्री से शिकायत

आर्यावर्त संवाददाता

कूरेभार/सुलतानपुर। विकासखंड कूरेभार की ग्राम पंचायत ढेसरुआ गुप्तारगंज में प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे एवं लाभार्थी चयन को लेकर उठे विवाद की शिकायत अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सुलतानपुर जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह तक पहुंच गई है। शिकायतकर्ता राजकुमार सोनी एवं सुमन जायसवाल ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल, जिलाधिकारी सुलतानपुर तथा खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कूरेभार को शिकायत भेजकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि, प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे के दौरान पात्रता निर्धारण में जान बूझ कर अनियमितताएं बरती गई हैं। आरोप है कि कुछ ऐसे लोगों को लाभार्थी सूची में शामिल किया गया है, जिनके पास पहले से पक्का मकान और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं, जबकि कई ऐसे परिवार, जो आज भी झोपड़ी, छप्पर अथवा टीन शेड के नीचे किसी तरह से अपना जीवनयापन करने को मजबूर हैं। यानी कि, पात्रों को योजना से वंचित कर अपात्रों को इसका लाभ दिया जा चुका है। शिकायतकर्ताओं ने मांग की है कि लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा सर्वे के दौरान अपनाई गई कार्यप्रणाली की निष्पक्ष समीक्षा की जाए। उनका कहना है कि यदि जांच में किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए और वास्तविक पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिलाया जाए। इस मामले को लेकर ग्रामीणों में भी चर्चा का माहौल गर्म है। हालांकि, शिकायत में लगाए गए आरोपों पर संबंधित अधिकारियों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही आरोपों की पुष्टि पूरी तरह से साफ हो पाएगी हो सकेगी।

183वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धापूर्वक याद किए गए डॉ. हैनीमैन

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमैन की 183वीं पुण्यतिथि पर नगर स्थित हैनीमैन चौराहा एवं हैनीमैन पार्क में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन, सुलतानपुर शाखा द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष प्रवीन कुमार अग्रवाल तथा विशिष्ट अतिथि अधिशासी अधिकारी लालचंद सरोज रहे। दोनों अतिथियों सहित एसोसिएशन के पदाधिकारियों एवं चिकित्सकों ने डॉ. हैनीमैन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. एस.के. तिवारी ने डॉ. हैनीमैन के जीवन एवं उनके चिकित्सा क्षेत्र में योगदान पर प्रकाश डालते हुए होम्योपैथी को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। मुख्य अतिथि प्रवीन कुमार अग्रवाल ने कहा कि शीघ्र ही हैनीमैन चौराहा एवं हैनीमैन पार्क का कायाकल्प और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा, जिससे नगर एवं जनपद को एक नई पहचान मिलेगी। इस अवसर पर एसोसिएशन के संरक्षक डॉ. रमाशंकर मिश्रा ने नगर पालिका अध्यक्ष को स्मृति-चिह्न भेंट कर सम्मानित किया।

कार्यक्रम में डॉ. राज रतन मिश्रा, डॉ. नीरज सिंह, डॉ. मनीष श्रीवास्तव, डॉ. अजय शर्मा, डॉ. विजय दुबे, डॉ. अमित सिंह, डॉ. संजय गुप्ता, डॉ. साहब सिद्दीकी, डॉ. गरिमा सिंह, डॉ. आशुतोष सिंह, डॉ. गौरव पांडेय, डॉ. के.एस. तिवारी, वार्ड सभासद दीप सिंह, मो. आरिफ, गगन श्रीवास्तव, शुभम पायातवाल सहित सैकड़ों चिकित्सक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे और श्रद्धांजलि अर्पित की।

मैनपुरी में पीएनजी सप्लाई बाधित, 100 से अधिक घरों में नहीं जले चूल्हे, सिलिंडर को भटके लोग

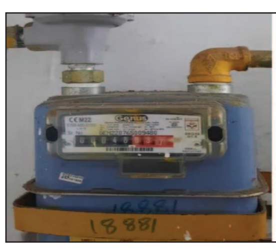

> फॉल्ट हुआ है। तकनीकी टीम मरम्मत करने में जुटी है। जल्द ही आपूर्ति को सुचारू करा लिया जाएगा।
>
> **- मो. अनस, तकनीकी प्रबंधक, शहरी क्षेत्र, एचपीसीएल**

आर्यावर्त संवाददाता

मैनपुरी। शासन स्तर से रसोई गैस सिलिंडर के झंझट से मुक्ति दिलाने और पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) को इसका जिम्मा दिया गया है। जिले में लगभग चार हजार से ज्यादा कनेक्शन बांटे जा चुके हैं।

जबकि शहर के एक हजार से अधिक घरों में यह सुविधा सुचारू भी हो चुकी है, लेकिन निगरानी व्यवस्था अभी मजबूत नहीं है। गुरुवार सुबह विभागीय दावों ने उपभोक्ताओं को फिर से झटका दे दिया। भूमिगत लाइन में फॉल्ट के कारण आवास विकास कालोनी में 100 से भी ज्यादा घरों की सप्लाई प्रभावित हो गई।

गुरुवार सुबह लगभग सात बजे अचानक आवास विकास कालोनी के सेक्टर एक में पीएनजी की सप्लाई पूरी तरह ठप हो गई। देखते ही देखते 100 से ज्यादा घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। सुबह का समय होने के कारण घरों में समस्या बढ़ गई। बच्चों को स्कूल भेजने और कामकाजी लोगों को दफ्तर के लिए नाश्ता-खाना तैयार करने की आपाधापी के बीच गैस गायब होने से लोग बेबस नजर आए।

कंपनी की ओर से बेहतर और निर्बाध आपूर्ति के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन संकट के समय इसकी कलई खुल गई। उपभोक्ताओं का आरोप है कि इतनी बड़ी तकनीकी खराबी आने के बाद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से किसी के मोबाइल पर न तो कोई मैसेज भेजा गया और न ही फोन के माध्यम से फॉल्ट की जानकारी दी गई।

उपभोक्ता काफी देर तक इस असमंजस में रहे कि आखिर समस्या क्या है? गैस सप्लाई बंद होने और कंपनी से कोई सूचना न मिलने के बाद लोगों को मजबूरी में वैकल्पिक प्रबंध तलाशने पड़े।

चीनी मिल में सेवानिवृत कर्मचारी का सम्मानपूर्वक विदाई समारोह आयोजित

सुल्तानपुर। इकलौती चीनी मिल सैदपुर में कार्यरत धीरेंद्र कुमार यादव सेवानिवृत होने पर उनके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा उन्हें सह सम्मान बुलाकर माला पहनाकर मिठाई के डिब्बों के साथ अंग वस्त्र देते हुए उन पुरानी यादों के साथ विदा किया। धीरेंद्र की आंखों में खुशी के पल के साथ में उनको दुख भी था। कार्यकाल के उन सभी लोगों की यादें जो साथ में लोगों के साथ बिताए थे। बहुत से ऐसे अधिकारी कर्मचारी उनके जीवन काल में आए और गए कुछ के साथ अच्छा कुछ के साथ खट्टा व्यवहार उनका बना रहा। लेकिन आज उन सब दिनों को याद करके उनकी आंखों में खुशी के पल के साथ कुछ रुसवाईयां भी रही जो वह अपनी जुबान से बयान नहीं कर सकते तमाम ऐसी परिस्थितियां आई गई लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बहुत वाक्य ऐसा भी है कि अपने पूरे जीवन काल में कुछ परिस्थितियां उनके विपरीत भी रही है।

बुलंदशहर में दुकान पर पहुंचा व्यापारी और तमंचे से सिर में गोली मारकर की आत्महत्या

आर्यावर्त संवाददाता

बुलन्दशहर। अनूपशहर में रेडीमेड गारमेंट्स व्यापारी ने गृहक्लेश व रुपयों के लेनदेन के चलते दुकान में तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। अनूपशहर के मुहल्ला मीरा निवासी 50 वर्षीय नदीम पुत्र हसमुददीन नगर के मोरी गेट में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान करता था। गुरुवार को सुबह वह दुकान पर गया था। सुबह दुकान में ही नदीम ने तमंचे से सिर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली की आवाज सुनते ही पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो नदीम का शव जमीन पर पड़ा था।

सिर में गोली मारने के कारण पूरा भेजा बाहर निकल आया। जानकारी मिलते ही कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार दुबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। मौके पर मौजूद पड़ोसियों ने बताया कि नदीम ने सुबह लगभग 9:00 बजे दुकान का शटर उठाया और अंदर जाकर शटर गिरा लिया। कुछ ही मिनट बाद गोली चलने की आवाज सुनाई दी, आवाज सुनकर पड़ोसियों ने मौके पर जाकर शटर उठाकर देखा तो नदीम का शव खून से लथपथ स्थिति में पड़ा हुआ था।

उन्होंने तत्काल नदीम के स्वजन तथा पुलिस को फोन द्वारा सूचना दी। नदीम ने कुछ माह पूर्व ही एक बेटा तथा एक बेटी की शादी की थी। उसके दो बेटा तथा तीन बेटियां हैं। लोगों ने बताया कि मामला लेन-देन तथा पारिवारिक कलह का प्रतीत होता है, किंतु इस संदर्भ में पुलिस कुछ नहीं बता सकी। बुलंदशहर से फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाने प्रारंभ कर दिए हैं। मौके पर ही तमंचा पड़ा हुआ था। पुलिस ने सभी साक्ष्य एकत्र कर नदीम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के बाद नदीम की दुकान के आगे सड़क पर कई घंटे तक भीड़ के कारण जाम जैसी स्थिति बनी रही। लोगों ने कहा कि नदीम व्यवहार कुशल स्वभाव का था। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया।

चिकित्सक दिवस पर उत्कृष्ट सेवा सम्मान से चिकित्सकों को किया सम्मानित

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

सुल्तानपुर। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर लायंस क्लब मिड टाउन, सुल्तानपुर की ओर से नगर के एक रेस्टोरेंट में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयोजन क्लब के अध्यक्ष प्रमोद पुरी एवं सचिव डॉ. राजेंद्र कपूर के नेतृत्व में हुआ। समारोह में जनपद के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित चिकित्सकों को अंगवस्त्र पहनाकर, स्मृति स्वरूप पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही क्लब की नई कार्यकारिणी का स्वागत एवं अभिनंदन भी किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए क्लब के सचिव डॉ. राजेंद्र कपूर ने कहा कि चिकित्सक समाज की रीढ़ हैं। वे बिना किसी जाति, धर्म, वर्ग अथवा भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति की सेवा करते हैं। विषम से विषम परिस्थितियों में भी डॉक्टर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मानव जीवन की रक्षा के लिए निरंतर कार्यरत रहते हैं। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। क्लब के अध्यक्ष प्रमोद पुरी ने कहा कि चिकित्सा सेवा मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। डॉक्टर अपने ज्ञान, अनुभव और समर्पण से समाज को स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का सम्मान कर लायंस क्लब मिड टाउन स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। समारोह में मंडल के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित सर्जन तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग संचालक डॉ. ए.के. सिंह, पूर्वांचल के सुप्रसिद्ध फिजिशियन एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव श्रीवास्तव, डॉ. सलिल श्रीवास्तव, डॉ. संगीता श्रीवास्तव, डॉ. हनुमान प्रसाद वैश्य, डॉ. डी.एस. मिश्रा, डॉ. आत्मजीत सिंह, डॉ. अनिल पांडेय, डॉ. संजय खत्री एवं डॉ. एस.के. गोयल सहित अनेक चिकित्सकों को अंगवस्त्र ओढ़ाकर तथा पौधा भेंट कर सम्मानित किया गया।

जालौन में ब्लॉक प्रमुख से विवाद मामले में आइएएस रिंकू सिंह बयान दर्ज, वीडियो फुटेज की होगी जांच

आर्यावर्त संवाददाता

उरई। जालौन तहसील से उरई सदर तहसील एसडीएम न्यायिक के पद पर स्थानांतरण के बाद भी आइएएस रिंकू सिंह की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं।

23 जून को जालौन ब्लॉक प्रमुख रामराजा निरंजन के कोल्ड स्टोरेज में निरीक्षण के दौरान हुए विवाद व उससे पूर्व लेखपाल, शिक्षकों की ओर से हुई शिकायतों के मामले में जांच कर रहे एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने रिंकू सिंह राही के बयान दर्ज कर लिए हैं।

इसमें उनकी ओर से सारे आरोप गलत बताए हैं। जांच अधिकारी को ब्लॉक प्रमुख की ओर से रिंकू सिंह के निरीक्षण के दौरान विवाद करने के दोनों वीडियो फुटेज भी सौंप दिए हैं। इसकी सत्यता की जांच साइबर सेल की ओर से की जाएगी।

ब्लॉक प्रमुख ने एसडीएम पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का निरीक्षण करने के दौरान उन्हें थप्पड़ मारने का प्रयास किया था, असफल रहने पर धक्का दे दिया था।

वीडियो फुटेज में रिंकू सिंह थप्पड़ मारने का प्रयास करते व दूसरे में मोबाइल छीन कर फेंकते हुए दिख रहे हैं। बिना काम के वेतन लेना नियम के विपरीत बता कर भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) से इस्तीफा देने वाले अधिकारी रिंकू सिंह राही की जालौन तहसील में पांच मई को तैनाती हुई थी।

अपनी तैनाती वाले क्षेत्र में वह मात्र 56 दिन ही रहे लेकिन इस बीच शिक्षकों, लेखपाल, वकील, प्रधान के साथ तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों ने उन पर अभद्र व्यवहार के कई आरोप लगाए और डीएम तक इन मामलों की करीब दस शिकायतें भी पहुंचीं। इससे तहसील के कार्यों के साथ जनगणना कार्य लगातार प्रभावित होता रहा। अपमानित होने के भय से कई अधिकारी, कर्मचारी अवकाश पर चले गए।

इन मामलों की जांच एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राज कर ही रहे थे कि 25 जून को फिर एक शिकायत जालौन ब्लाक प्रमुख रामराजा निरंजन ने डीएम से की। उन्होंने बताया था कि उनके कोल्ड स्टोरेज की जांच करने पहुंचे एसडीएम ने आते ही तेज में गेट खोलने को कहा। देरी होने पर वहां खड़े ब्लॉक प्रमुख को थप्पड़ मारने का प्रयास किया, असफल होने पर दोनों हाथों से धक्का दिया जिससे ब्लाक प्रमुख गिरते बचे।

इसकी जांच भी एडीएम वित्त एवं राजस्व को सौंपी गई थी। इस मामले के साथ पूर्व मामलों की प्रारंभिक जांच के आधार पर ही रिंकू सिंह को तीस जून को जालौन तहसील से हटा कर उरई सदर तहसील में एसडीएम न्यायिक के पद पर स्थानांतरित कर दिया गया।

एसडीएम की तैनाती के दौरान तहसील में विवादों के चलते विरासत, निवास प्रमाण पत्र, अंश निर्धारण सहित कई राजस्व मामलों के निस्तारण की गति अपेक्षित नहीं थी। जनगणना कार्य के दौरान शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से यहां तक कहा था कि काम करने के बावजूद उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता है।

एडीएम वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने बताया कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट डीएम को पहले ही प्रेषित की जा चुकी है, एसडीएम के बयान हो चुके हैं, इसमें उनकी ओर से कहा गया है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वह केवल निरीक्षण पर असर डालने के लिए गलत लगाए जा रहे हैं।

ब्लॉक प्रमुख की ओर से दो वीडियो फुटेज जांच टीम को सौंप दिए गए हैं। मामले में आम नागरिक, व्यापारियों के भी बयान दर्ज होने हैं।

इस मामले में एसडीएम न्यायिक रिंकू सिंह राही का कहना है कि जांच टीम का वह पूरा सहयोग कर रहे हैं, उनकी ओर से कुछ भी गलत नहीं किया गया है।

मानकविहीन कोचिंग संस्थानों का शुरू हुआ संचालन

सुल्तानपुर। पिछले महीने लखनऊ के एक कोचिंग संस्थान की बिल्डिंग में आग लग जाने के कारण कई बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जिससे कोचिंग संस्थानों के ऊपर शासन और प्रशासन की नजर पड़ी, मानक विहीन कोचिंग संस्थान बंद कराए जाने लगे, कोचिंग संचालक ताला लगा कर कुछ दिन के लिए बच्चों की छुट्टी कर खुद आराम करने लगे। और मामले को ठंडे बस्ते में जाने का इंतजार करने लगे। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से निरीक्षण करते हुए चेतावनी जारी करते रहे कि बिना मानक पूरे कोई भी कोचिंग संस्थान संचालित नहीं हो सकता। जिला विद्यालय निरीक्षक और अग्नि शमन विभाग भी कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी कर कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन करने का निर्देश जारी करने लगे। किंतु जैसे ही समय बीतता जा रहा है कोचिंग संस्थानों का ताला भी धीरे धीरे खुलने लगा और प्रशासन का आदेश सिर्फ कागजों तक ही सीमित हो चुका है।

प्रदेशव्यापी वृक्षारोपण सप्ताह के तहत वृक्षारोपण एवं आम पौध वितरण कार्यक्रम आयोजित

सुल्तानपुर। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृक्षारोपण सप्ताह (01 से 07 जुलाई, 2026) के अंतर्गत लम्भुआ ब्लॉक के तुलसी नगर वार्ड स्थित ग्राम पठखौली में वृक्षारोपण एवं आम पौध वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, हरित आवरण में वृद्धि करना तथा विशेष रूप से छात्र-छात्राओं और आमजन को प्रकृति के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम के दौरान आम, मौलश्री, महुआ, पीपल एवं पाकड़ सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही विद्यालय के छात्र-छात्राओं को आम के पौधे वितरित कर उन्हें पौधारोपण के साथ-साथ पौधों की नियमित देखभाल एवं संरक्षण के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक एवं सामाजिक जिम्मेदारी है।

1.5 घंटे का सफर 45 मिनट में होगा पूरा... 13 जुलाई से शुरू होगा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे, कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को भी मंजूरी

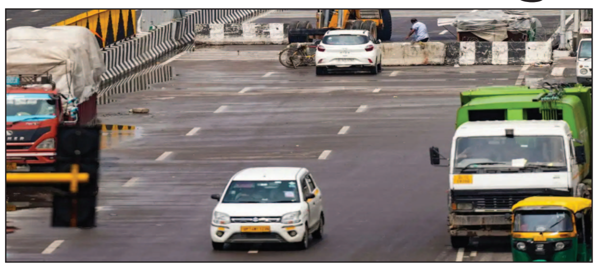

> **साढ़े तीन घंटे का सफर डेढ़ घंटे में होगा पूरा**
>
> अभी कानपुर से कबरई तक पहुंचने में करीब साढ़े तीन घंटे लगते हैं, लेकिन नए हाईवे के बनने के बाद यही सफर डेढ़ से दो घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इससे यात्रियों का समय और ईंधन दोनों बचेंगे, जबकि उद्योग, कृषि, लॉजिस्टिक्स और व्यापारिक गतिविधियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अनुसार कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले तीन महीनों में भूमि अधिग्रहण और टेंडर प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। इन दोनों परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश का सड़क नेटवर्क और मजबूत होगा। एक तरफ राजधानी लखनऊ और कानपुर के बीच हाई-स्पीड कनेक्टिविटी मिलेगी, तो दूसरी ओर बुंदेलखंड को आधुनिक एक्सप्रेसवे नेटवर्क से जोड़कर क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

आर्यावर्त संवाददाता

कानपुर। उत्तर प्रदेश को सड़क कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। एक ओर 13 जुलाई से बहुप्रतीक्षित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को भी मंजूरी दे दी है। इन दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से न सिर्फ यात्रा का समय कम होगा, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक, व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को भी नई रफ्तार मिलेगी।

करीब 4,700 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ के कानपुर रोड क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। इसी दौरान इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर बनने वाले नए फ्लाईओवर का शिलान्यास भी किया जाएगा।

कितना लंबा है लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे?

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे कुल 63 किमी लंबा है। 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे को भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। परियोजना में 18 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन और 45 किलोमीटर ग्रीनफील्ड कॉरिडोर शामिल है। इसके शुरू होने के बाद लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रैफिक का दबाव करीब 70 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है। इससे दोनों शहरों के बीच सफर तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक होगा। अभी लखनऊ से कानपुर जाने में करीब 1.5 से 2.5 घंटे लगते हैं। एक्सप्रेसवे शुरु हो जाने के बाद यह सफर 45 से 60 मिनट का रह जाएगा।

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर कितना देना होगा टोल?

एक्सप्रेसवे पर चार टोल प्लाजा बनाए गए हैं। वार्षिक फास्टैग योजना का लाभ लेने वाले वाहन चालकों को केवल 15 रुपये का टोल देना होगा, जबकि सामान्य कार चालकों के लिए एक तरफ का टोल 275 रुपये तय किया गया है। 24 घंटे के भीतर वापसी करने पर 415 रुपये का शुल्क देना होगा। सुरक्षा के लिए पूरे एक्सप्रेसवे पर एएनपीआर और पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वाहनों की निगरानी और यातायात प्रबंधन अधिक प्रभावी होगा।

कितने किमी होगा कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे?

इसी बीच केंद्र सरकार ने कानपुर और बुंदेलखंड को जोड़ने वाले 123 किलोमीटर लंबे कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को भी मंजूरी दे दी है। लगभग 7,145 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे कानपुर के रमईपुर के पास मगरासा से शुरू होकर महोबा जिले के कबरई तक जाएगा। यह आगे बांदा-सागर हाईवे और भोपाल-मुंबई कॉरिडोर से भी जुड़ेगा। यह परियोजना खास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग-34 लंबे समय से सड़क हादसों के लिए बदनाम रहा है। पिछले पांच वर्षों में इस मार्ग पर करीब 994 सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 604 लोगों की मौत और लगभग 890 लोग घायल हुए। नए ग्रीनफील्ड हाईवे से इन हादसों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है।

ग्रीनफील्ड हाईवे पर बनेंगे 16 पुल

ग्रीनफील्ड हाईवे पर 16 बड़े पुल, एक रेलवे ओवरब्रिज और दोनों ओर लगभग 12 किलोमीटर लंबी सर्विस रोड बनाई जाएगी। एक्सेस कंट्रोल व्यवस्था लागू होने से स्थानीय और लंबी दूरी के वाहनों की आवाजाही अलग-अलग होगी, जिससे सड़क सुरक्षा और बेहतर होगी।

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने डेलॉयट को लगाई फटकार, बोले–

डेढ़ साल में नहीं दिखे परिणाम, जुलाई में महाभियान और अगस्त में मुंबई रोड शो के निर्देश

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में पर्यटन क्षेत्र की भूमिका को और प्रभावी बनाने के लिए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने डेलॉयट संस्था की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में संस्था की प्रगति संतोषजनक नहीं रही और अब केवल योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनके परिणाम धरातल पर भी दिखाई देने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि प्रस्तावित कार्ययोजनाओं पर तत्काल अमल शुरू किया जाए तथा इस माह पर्यटन स्थलों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए विशेष महाभियान चलाया जाए। साथ ही अगस्त के मध्य में मुंबई में निवेश आकर्षित करने के उद्देश्य से रोड शो आयोजित करने के निर्देश भी दिए।गोमतीनगर स्थित पर्यटन भवन के सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में मंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए तैयार की गई कार्ययोजनाओं और भविष्य की रणनीतियों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात, महानिदेशक पर्यटन वेदपति मिश्र, पर्यटन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा डेलॉयट संस्था के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।बैठक के दौरान जयवीर सिंह ने डेलॉयट को निर्देश दिया कि काशी, विंध्याचल धाम और नैमिषारण्य में निवेश बढ़ाने तथा पर्यटन संसाधनों के प्रभावी प्रचार-प्रसार के लिए तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना तैयार करने के साथ-साथ उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि पर्यटन क्षेत्र में निवेश और पर्यटकों की संख्या में वास्तविक वृद्धि हो सके।पर्यटन मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार और बेहतर संपर्क सुविधाओं के कारण पर्यटन क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। उन्होंने 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) की तर्ज पर 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कल्चर' (ओडीओसी) को भी पर्यटन से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि प्रत्येक जिले की सांस्कृतिक और पारंपरिक विशेषताओं का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा सके। उन्होंने प्रदेश के 12 पर्यटन परिपथों से जुड़े स्थलों का सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और रोड शो के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के निर्देश दिए।डेलॉयट संस्था के प्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि शीघ्र ही वाराणसी, विंध्याचल धाम और नैमिषारण्य में पर्यटकों के अनुभवों पर आधारित विशेष प्रचार अभियान शुरू किया जाएगा। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि पर्यटन से जुड़े सभी आंकड़े वास्तविक और प्रमाणिक होने चाहिए, ताकि भविष्य की योजनाएं सही आधार पर तैयार की जा सकें।बैठक में पर्यटन विभाग के होटलों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने तथा पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमरों की क्षमता बढ़ाने की रणनीति तैयार करने के भी निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि अयोध्या, लखनऊ और मथुरा में पर्यटन क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश प्राप्त हुआ है। मंत्री ने कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने में पर्यटन क्षेत्र मजबूत विकास इंजन की भूमिका निभा रहा है। इसके लिए बुनियादी ढांचे के विस्तार, निजी निवेश को बढ़ावा देने और पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

सआदत अली खां मकबरे की फसाड लाइट चोरी का खुलासा, तीसरा आरोपी गिरफ्तार

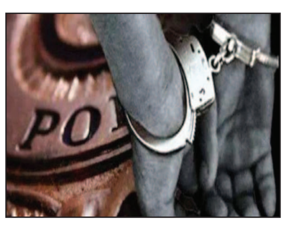

आर्यावर्त क्रांति ब्यूरो

लखनऊ। राजधानी के ऐतिहासिक सआदत अली खां मकबरे से फसाड लाइटें चोरी करने के मामले में कैसरबाग पुलिस ने तीसरे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की निशानदेही पर फिलिप्स कंपनी की पांच चोरी की गई फसाड लाइटें भी बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार इस मामले में आरोपी के दो साथी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे आरोपी की काफी समय से तलाश की जा रही थी।पुलिस के मुताबिक, 16 मई 2026 को रिजवान हुसैन ने कैसरबाग थाने में तहरीर देकर बताया था कि सआदत अली खां मकबरा परिसर में लगी फसाड लाइटें अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक चंदन कुमार मिश्रा कर रहे थे।जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल वांछित आरोपी स्वास्थ्य भवन चौराहे के पास स्थित ग्लोब पार्क में घूम रहा है और किसी नई वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही कैसरबाग पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर संदिग्ध युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम अंशू कश्यप (19 वर्ष) निवासी बलवरिया कुतुबपुर, मनकामेश्वर मंदिर के पीछे, थाना हसनगंज बताया।

सातवें वर्ष भी बिजली दरें स्थिर, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत : ए.के. शर्मा

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (यूपीईआरसी) द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी टैरिफ आदेश पर नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि लगातार सातवें वर्ष सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरों को यथावत रखना प्रदेश के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की उपभोक्ता हितैषी नीतियों का परिणाम बताया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा क्षेत्र में सुधार, पारदर्शिता, हरित ऊर्जा को बढ़ावा और आधुनिक विद्युत अवसंरचना के विकास की दिशा में जो पहल हुई है, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रभावी ढंग से लागू किया है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश बिजली उत्पादन, आपूर्ति, वितरण सुधार और उपभोक्ता सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है।ए.के. शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए टैरिफ सब्सिडी बढ़ाकर 20,400 करोड़ रुपये कर दी गई है, जबकि पिछले वर्ष यह 17,100 करोड़ रुपये थी। इससे लाइफलाइन उपभोक्ताओं, ग्रामीण एवं शहरी गरीब परिवारों, निजी नलकूप संचालकों और ग्रामीण मीटर्ड उपभोक्ताओं को पहले की तरह राहत मिलती रहेगी।उन्होंने कहा कि यूपीईआरसी ने लगभग 2,580 करोड़ रुपये के रेगुलेटरी गैप के बावजूद बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की। आयोग ने माना कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन और राज्य के वितरण निगमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन तथा उपलब्ध रेगुलेटरी सरप्लस के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार डालने की आवश्यकता नहीं है। इसे उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में वित्तीय अनुशासन और सुधारों का सकारात्मक परिणाम बताया।ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों को भी लगातार प्रोत्साहित कर रही है। ग्रीन एनर्जी अतिरिक्त टैरिफ को पूर्ववत रखा गया है। साथ ही बैटरी स्वैपिंग स्टेशन और बैटरी ऐज ए सर्विस (बीएएएस) प्रदाताओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक सौर ऊर्जा अवधि में ईवी चार्जिंग पर 20 प्रतिशत कम टैरिफ की व्यवस्था की गई है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश में रिकॉर्ड विद्युत मांग की सफल आपूर्ति, ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क का विस्तार, तकनीकी सुधार, लाइन हानियों में कमी तथा उपभोक्ता सेवाओं में पारदर्शिता के कारण उत्तर प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में देश के लिए एक आदर्श मॉडल बनकर उभरा है। सरकार का लक्ष्य केवल निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना ही नहीं, बल्कि बिजली को आम उपभोक्ता की पहुंच में बनाए रखना भी है। इसी उद्देश्य से लगातार सात वर्षों से बिजली की दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई है।ए.के. शर्मा ने कहा कि 'विकसित भारत' और 'विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करने में ऊर्जा क्षेत्र की यह उपलब्धि महत्वपूर्ण है।

• संक्षेप •

मड़ियांव में देर रात ताबड़तोड़ फायरिंग, युवक पर जानलेवा हमला

लखनऊ। राजधानी के मड़ियांव थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गनीमत रही कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और युवक बाल–बाल बच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के साथ वरिष्ठ अधिकारी भी तत्काल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई की रात करीब 10:30 बजे मड़ियांव थाना क्षेत्र स्थित एकता पब्लिक स्कूल, प्रीति नगर के पास गोली चलने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली। सूचना मिलते ही मड़ियांव थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए साक्ष्य जुटाए और आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की।प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रीति नगर निवासी कौशल पांडे अपने कुछ साथियों के साथ स्कूल के पास खड़ा था। इसी दौरान आशुतोष तिवारी और गौरव बाजपेयी मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे। आरोप है कि दोनों ने कौशल पांडे को निशाना बनाकर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली किसी को नहीं लगी और कौशल पांडे सुरक्षित बच गया। घटना के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।फायरिंग की घटना के बाद इलाके में अफरा–तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने गोली चलने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज, थाना प्रभारी मड़ियांव और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी।पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे के कारणों की जांच की जा रही है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुरानी रंजिश सहित अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा।

सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने पकड़ा फाइबर केबल चोर गिरोह

लखनऊ। राजधानी के सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर केबल चोरी करने वाले दो शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से करीब 612 फीट लंबी, लगभग तीन कुंतल वजनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, एक वायर कटर तथा एक एक्सयूवी–500 कार बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी की गई केबल को औने–पौने दामों में बेचकर आर्थिक लाभ कमाते थे।यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर और संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। अभियान का पर्यवेक्षण पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) अमित कुमार आनंद, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) रल्लापल्ली वसंथ कुमार तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज ऋषभ यादव ने किया। अतिरिक्त निरीक्षक विनोद कुमार पांडेय के नेतृत्व में सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार किया।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई को सूचना मिली थी कि कृष्णागांव के सामने आउटर रिंग रोड नहर के पास एक कार में दो युवक चोरी की गई ऑप्टिकल फाइबर केबल के बंडल लेकर खड़े हैं और राहगीरों से उसे बेचने की बातचीत कर रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों संदिग्धों को पकड़ लिया।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मारूफ (24) निवासी बाबागंज, थाना रूपडीह, जनपद बहराइच, हाल निवासी कांशीराम कॉलोनी, लौलेही, चिनहट तथा शानू (24) निवासी नंदपुर डूडा कॉलोनी, थाना चिनहट के रूप में हुई है। पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि एक–दो दिन पहले उन्होंने चिनहट स्थित एमिटी कॉलेज के पास से ऑप्टिकल फाइबर केबल चोरी की थी और उसे बेचने जा रहे थे।

रालोद संसदीय बोर्ड में शामिल होने पर अनिल दुबे का भव्य स्वागत

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव अनिल दुबे को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा रालोद संसदीय बोर्ड का सदस्य मनोनीत किए जाने पर गुरुवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनका भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम से पहले अनिल दुबे ने पार्टी नेताओं के साथ भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।स्वागत समारोह का आयोजन एवं संचालन व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर अनिल दुबे ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन पर जताए गए विश्वास पर वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ खरा उतरने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल किसानों, युवाओं, मजदूरों और समाज के सभी वर्गों की आवाज को मजबूती से उठाने के लिए प्रतिबद्ध है तथा संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य किया जाएगा। उन्होंने स्वागत एवं सम्मान के लिए सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद भी ज्ञापित किया।प्रदेश पदाधिकारियों ने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि अनिल दुबे पूर्वांचल, मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में लोकप्रिय, संघर्षशील एवं कर्मठ नेता के रूप में अपनी अलग पहचान रखते हैं। उनके संसदीय बोर्ड में शामिल होने से इन क्षेत्रों में पार्टी संगठन को नई मजबूती मिलेगी और आगामी चुनावों में राष्ट्रीय लोकदल अधिक सशक्त होकर उभरेगा।वक्ताओं ने कहा कि संसदीय बोर्ड में अनिल दुबे का मनोनयन उनके लंबे संगठनात्मक अनुभव, समर्पण और पार्टी के प्रति निष्ठा का सम्मान है। उनके अनुभव का लाभ संगठन को मिलेगा तथा पार्टी को जमीनी स्तर पर और अधिक मजबूती प्राप्त होगी। कार्यक्रम में उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पार्टी नेतृत्व के निर्णय का स्वागत करते हुए संगठन को और सशक्त बनाने का संकल्प भी लिया।समारोह में युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल, एससी-एसटी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भगवती प्रसाद सूर्यवंशी, प्रोफेशनल मंच के प्रदेश अध्यक्ष अम्बुज पटेल, राष्ट्रीय सचिव आर.एन. शुक्ला, श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश पाल धनगर सहित रजनीकांत मिश्रा, बी.एल. प्रेमी, चौधरी भूपाल सिंह, रामावती तिवारी, प्रीति श्रीवास्तव, चंद्रकांत अवस्थी, राव इकबाल, प्रमोद शुक्ला, पी.के. पाठक, राजकुमार ओझा, माया देवी, अनीता यादव, बिपिन द्विवेदी, शफीक और मुकेश वर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लखनऊ पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी साइबर कार्रवाई, समिट बिल्डिंग में चल रहे अंतरराष्ट्रीय फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए विभूतिखंड स्थित समिट बिल्डिंग में संचालित एक संगठित अंतरराष्ट्रीय साइबर फ्रॉड कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। संयुक्त कार्रवाई में कुल 119 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 103 लैपटॉप, 68 एप्पल आईफोन, 116 हेडफोन, 109 मोबाइल फोन और बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह मुख्य रूप से अमेरिका के नागरिकों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की साइबर ठगी को अंजाम देता था। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देशन, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) अपर्णा कुमार के पर्यवेक्षण तथा पुलिस उपायुक्त अपराध अनिल कुमार यादव के मार्गदर्शन में की गई। अभियान का नेतृत्व अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरन यादव (आईपीएस) ने किया। साइबर क्राइम सेल और थाना साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त टीम ने 1 जुलाई की देर शाम समिट बिल्डिंग पर छापा मारकर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया।पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह आधुनिक इंटरनेट आधारित कॉलिंग तकनीक, वीओआईपी सिस्टम और प्रतिबंधित आईबीम डायलर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता था। आरोपी स्वयं को अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, पेपाल, नेटफ्लिक्स और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों का अधिकृत प्रतिनिधि या कस्टमर सपोर्ट अधिकारी बताकर अमेरिकी नागरिकों को कॉल करते थे। उन्हें बताया जाता था कि उनके बैंक खाते, डिजिटल वॉलेट या पहचान से जुड़ी गंभीर समस्या सामने आई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।जब पीड़ित डर जाता था, तब कॉल को दूसरे स्तर पर स्थानांतरित कर आरोपी स्वयं को एफबीआई, फेडरल ट्रेड कमीशन (FTC), यूएस मार्शल सर्विस, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग और अमेरिकी अदालतों का अधिकारी बताकर गिरफ्तारी और जांच का भय दिखाते थे। भरोसा दिलाने के लिए फर्जी कोर्ट ऑर्डर, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आईडेंटिटी थेफ्ट रिपोर्ट और एनडीए जैसे नकली दस्तावेज ई-मेल से भेजे जाते थे, जो देखने में असली सरकारी दस्तावेज जैसे लगते थे।जांच में पता चला कि पूरा कॉल सेंटर एक कॉर्पोरेट कंपनी की तरह संचालित हो रहा था। इसमें अलग-अलग टीमें बनाई गई थीं। पहली टीम फर्जी संदेश भेजकर लोगों को डराती थी कि उनके खाते का इस्तेमाल बाल यौन शोषण सामग्री, मादक पदार्थ तस्करी या आतंकी गतिविधियों में हुआ है। दूसरी टीम कॉल रिसीव कर विश्वास जीतती थी। तीसरी टीम बैंक खातों और धनराशि की जानकारी जुटाती थी और चौथी टीम पीड़ितों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर गिफ्ट कार्ड, क्रिप्टोकरेंसी या नकदी के रूप में पैसा वसूलती थी।पुलिस के अनुसार गिरोह विभिन्न राज्यों से बीपीओ और इंटरनेशनल कॉलिंग का अनुभव रखने वाले युवाओं की भर्ती करता था। उन्हें फर्जी कंपनी "सोलारिस सॉल्यूशंस" के नाम पर रहने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोई वैधानिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता था। ठगी की रकम सीधे बैंक खातों में लेने के बजाय गिफ्ट कार्ड, डिजिटल वाउचर और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से प्राप्त की जाती थी, ताकि धन के स्रोत और अंतिम लाभार्थी को छिपाया जा सके।

अतिक्रमण पर नगर निगम का बड़ा प्रहार : डालीगंज से आलमबाग तक चला बुलडोजर

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने गुरुवार को व्यापक अभियान चलाते हुए दो प्रमुख जोनों में बड़ी कार्रवाई की। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर जोन-03 और जोन-05 में सड़कों, फुटपाथों और सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया। अभियान के दौरान 35 से अधिक अस्थायी दुकानें हटाई गईं, कई ठेले, गुमटियां और काउंटर जब्त किए गए तथा अतिक्रमण, गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन के उपयोग के मामलों में कुल 19,500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। कार्रवाई के दौरान नगर निगम अधिकारियों के साथ पुलिस बल भी मौजूद रहा।नगर निगम की प्रवर्तन टीम ने सबसे पहले जोन-03 के अंतर्गत ताड़ीखाना स्थित पल्टन छावनी क्षेत्र में लकड़ी व्यापारियों द्वारा सड़क और सार्वजनिक स्थानों पर किए गए अतिक्रमण को हटाया। इसके बाद महानगर से साहू एजेंसी तक दोनों ओर की पटरियों पर अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाया गया। डालीगंज वार्ड स्थित लकड़ी मंडी में भी विशेष कार्रवाई करते हुए विभागीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया।डालीगंज क्रॉसिंग के निकट बबली राजा एवं अन्य लोगों द्वारा विभागीय भूमि पर अस्थायी दुकानें लगाकर किए गए कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 20 से 35 अस्थायी दुकानें हटाई गईं। गमलों के माध्यम से किए गए अतिक्रमण को भी हटाया गया। इस दौरान संबंधित अतिक्रमणकारियों से 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। नगर निगम ने भविष्य में दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए स्थानीय पुलिस को भी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेज दिया है।दूसरी ओर जोन-05 के अंतर्गत रामजीलाल सरदार पटेल नगर वार्ड स्थित मौनी बाबा मार्केट, आलमबाग और आसपास के क्षेत्रों में भी विशेष अभियान चलाया गया। यहां फुटपाथों और सड़कों पर अवैध रूप से लगाए गए 6 ठेले, 4 गुमटियां और 8 काउंटर हटाए गए। इसके अलावा 3 काउंटर, एक रिक्शा ट्रॉली और एक लोहे की गुमटी को जब्त कर नगर निगम के कब्जे में लिया गया।कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण करने वालों को भविष्य में दोबारा कब्जा न करने की कड़ी चेतावनी दी गई तथा 2,500 रुपये का शमन शुल्क वसूला गया। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने और प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग करने वालों के विरुद्ध भी सख्ती बरती गई। इस दौरान 15,000 रुपये का अतिरिक्त शमन शुल्क वसूलकर स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के नियमों का पालन सुनिश्चित कराया गया।जोन-03 की कार्रवाई जोनल अधिकारी मनोज यादव के निर्देशन में प्रवर्तन दल-296 द्वारा की गई, जबकि जोन-05 में जोनल अधिकारी विनीत कुमार सिंह के नेतृत्व में कर अधीक्षक सभाजीत सिंह, जोनल सेनेटरी अधिकारी सचिन सक्सेना, राजस्व निरीक्षक विवेक मिश्रा, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सुभाष चौधरी, प्रवर्तन दल-296 तथा पुलिस बल की मौजूदगी में अभियान चलाया गया।नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि राजधानी को अतिक्रमण मुक्त बनाने, यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और नागरिकों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों पर पुलिस का सख्त शिकंजा, 1,316 लोगों का चालान

लखनऊ। पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ ने सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, हुड़दंग करने और आमजन, विशेषकर महिलाओं के लिए असुविधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए 1,316 लोगों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई की। अभियान के दौरान शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 256 स्थानों पर 6,974 लोगों की जांच की गई। पुलिस आयुक्त अमरेन्द्र कुमार सेंगर के निर्देश तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) बबलू कुमार के पर्यवेक्षण में 30 जून और 1 जुलाई की रात 10 बजे से मध्यरात्रि तक सभी जोनों में अभियान चलाया गया। सभी पुलिस उपायुक्तों के नेतृत्व में सहायक पुलिस आयुक्तों और थाना प्रभारियों की टीमों ने सड़कों, पार्कों, बाजारों, बस अड्डों, चौराहों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सघन जांच की।

रहीमाबाद में फायरिंग और मारपीट के मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

आर्यावर्त संवाददाता

लखनऊ। रहीमाबाद थाना क्षेत्र में गाली-गलौज, लाठी-डंडों से मारपीट और जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त 32 बोर का कारतूस का खोखा, एक होल्स्टर, एक सैमसंग जेड फोल्ड-07 मोबाइल फोन तथा एक बलेनो और एक महिंद्रा थार वाहन भी बरामद किए हैं। आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।पुलिस के अनुसार, 1 जुलाई 2026 को पीड़िता द्वारा थाना रहीमाबाद में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया था कि विपक्षी पक्ष ने उसके और उसके परिवार के साथ गाली-गलौज की, लाठी-डंडों से मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। शिकायत के आधार पर थाना रहीमाबाद में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रारंभिक मुकदमे में अनिल, हरगोविंद, बबलू तथा 15 से 20 अज्ञात लोगों को नामजद किया गया था।विवेचना के दौरान पुलिस ने पीड़ित के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल के निरीक्षण, वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों का परीक्षण किया। जांच में कुलदीप कुमार, राम सिंह और मनीष की संलिप्तता भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर उन्हें 2 जुलाई की रात करीब 2:10 बजे गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य भी बरामद किए। इनमें 32 बोर का एक कारतूस का खोखा, एक होल्स्टर, सैमसंग जेड फोल्ड-07 मोबाइल फोन, बलेनो कार (संख्या यूपी-32-क्यूबी-6446) तथा काले रंग की महिंद्रा थार (संख्या यूपी-32-पीपी-4141) शामिल हैं।

क्या हम विकास और विनाश के बीच संतुलन साध पाएंगे?

वेनेजुएला में हाल में आए भीषण भूकम्प ने केवल एक देश को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को झकझोर दिया है। मृतकों और लापता लोगों की संख्या समय के साथ बदलती रही हो, लेकिन त्रासदी की भयावहता निर्विवाद है। हजारों परिवार अपने प्रियजनों को खोने की असहनीय पीड़ा से गुजर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक अवसर पर पूरी दुनिया संवेदना व्यक्त करती है, राहत सामग्री भेजती है, सहायता अभियान चलाती है, लेकिन एक प्रश्न बार-बार हमारे सामने खड़ा हो जाता है-क्या हम हर बड़ी आपदा से कोई स्थायी सबक सीखते हैं या फिर कुछ दिनों की चर्चा और शोक के बाद सब कुछ भुलाकर पुनः उसी लापरवाह विकास-यात्रा एवं प्रकृति की घोर उपेक्षा पर निकल पड़ते हैं? प्राकृतिक आपदाएं कभी कैलेंडर देखकर नहीं आतीं। वे न देश चुनती हैं, न मौसम और न समय। जब धरती कांपती है, नदियां उफान पर आती हैं, पहाड़ दरकते हैं या समुद्र विकराल रूप धारण कर लेता है, तब विकास के बड़े-बड़े दावे, ऊंची-ऊंची इमारतें और तकनीकी उपलब्धियों का अहंकार कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाता है। ऐसे समय में किसी देश की वास्तविक शक्ति उसकी आर्थिक समृद्धि नहीं, बल्कि उसकी पूर्व तैयारी, संवेदनशील शासन व्यवस्था और जागरूक नागरिक होते हैं। वेनेजुएला की त्रासदी ने एक सकारात्मक पक्ष भी सामने रखा। आधुनिक तकनीक ने कुछ क्षेत्रों में लोगों को भूकम्प के झटके महसूस होने से कुछ सेकंड पहले चेतावनी दी। सुनने में यह समय बहुत कम प्रतीत होता है, लेकिन आपदा की घड़ी में यही कुछ सेकंड जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी तय कर सकते हैं। विज्ञान इस दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे प्रारंभिक चेतावनी तंत्र अधिक सटीक, अधिक तेज और अधिक व्यापक बनाए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों का जीवन सुरक्षित रह सके। भारत के लिए यह विषय केवल एक अंतरराष्ट्रीय समाचार नहीं है। हमारा देश स्वयं भूकम्प, बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने, चक्रवात और सुनामी जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। 1993 का लातूर भूकम्प, 2001 का भुज भूकम्प, 2004 की सुनामी, 2013 की केदारनाथ त्रासदी, 2023 की जोशीमठ भू-धंसाव की घटनाएं तथा हिमालयी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं आज भी हमारी स्मृतियों में जीवित हैं। इन सभी घटनाओं का एक ही संदेश है-प्रकृति को कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। वैज्ञानिक आज भी यह निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस दिन, किस समय और किस स्थान पर भूकम्प आएगा, लेकिन वे वर्षों से यह चेतावनी अवश्य देते रहे हैं कि भारत का लगभग साठ प्रतिशत भूभाग किसी न किसी स्तर के भूकम्पीय जोखिम वाले क्षेत्र में आता है। हिमालयी क्षेत्र, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर-पूर्व, गुजरात और अनेक अन्य क्षेत्र विशेष रूप से संवेदनशील माने जाते हैं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि यदि भूकम्प की सटीक भविष्यवाणी संभव नहीं है, तो भी पूर्व तैयारी पूरी तरह संभव है। दुर्भाग्य यह है कि हम तैयारी की अपेक्षा आपदा के बाद राहत और पुनर्वास पर अधिक ध्यान देते हैं। आज देश के लगभग हर शहर में कंक्रीट के विशाल जंगल तेजी से खड़े हो रहे हैं। बहुमंजिला आवासीय परिसर, व्यावसायिक भवन, गगनचुंबी टावर और स्मार्ट सिटी विकास की नई पहचान बन चुके हैं। मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और अब जयपुर जैसे शहर भी ऊंची-ऊंची इमारतों की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या इन भवनों की मजबूती केवल सामान्य परिस्थितियों के लिए है या किसी बड़ी प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए भी? किसी भी भवन की वास्तविक परीक्षा तब होती है जब धरती कांपती है, जब अचानक बाढ़ आती है, जब तेज हवाएं चलती हैं या जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है। यदि उस समय भवन लोगों की जान बचा सके, तभी उसे वास्तविक विकास का प्रतीक माना जाना चाहिए। केवल ऊंचाई, चमक-दमक और आधुनिक सुविधाएं किसी भवन को सुरक्षित नहीं बनातीं। भारत में भूकम्परोधी निर्माण के लिए मानक और नियम मौजूद हैं। भारतीय मानक ब्यूरो ने स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। समस्या नियमों की कमी नहीं, बल्कि उनके अनुपालन की है। क्या प्रत्येक बहुमंजिला इमारत वास्तव में उन्हीं मानकों के अनुरूप निर्मित हो रही है? क्या निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच होती है? क्या निर्माण के बाद संरचनात्मक सुरक्षा का स्वतंत्र परीक्षण किया जाता है? यदि इन प्रश्नों का उत्तर पूरी तरह संतोषजनक नहीं है, तो चिंता स्वाभाविक है। निर्माण क्षेत्र में बढ़ती अनियमितताओं और भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बनाया है। अनेक बार भू-माफिया, बिल्डर लॉबी और लाभ-लोलुप तत्व पर्यावरणीय नियमों की अवहेलना करते हुए हरित क्षेत्रों, जलाशयों, नदी तटों और भू-संवेदनशील क्षेत्रों तक में निर्माण कर देते हैं। बाद में यही निर्माण किसी त्रासदी का कारण बनते हैं। नोएडा में अवैध रूप से निर्मित सुपरटेक ट्विन टावरों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ध्वस्त किया जाना इस बात का प्रतीक है कि किस प्रकार नियमों की अनदेखी कर निर्माण कार्य किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यदि कोई निर्माण अवैध था, तो उसे बनने की अनुमति किसने दी? निर्माण पूरा होने तक प्रशासन मौन क्यों रहा? क्या विकास के नाम पर कुछ लोगों के आर्थिक लाभ के लिए लाखों नागरिकों के जीवन को जोखिम में डाला जा सकता है?

प्रकृति की गोद में बसा जशपुर का अनुपम पर्यटन स्थल 'रानीदाह'

जहां हरियाली, कल-कल बहता झरना और लोककथाओं का अद्भुत संगम पर्यटकों को करता है मंत्रमुग्ध

रानीदाह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोककथाओं और जनश्रुतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

सुनील त्रिपाठी, नूतन सिदार

छत्तीसगढ़ का जशपुर जिला अपनी प्राकृतिक संपदा, घने वनों, पहाड़ियों और मनमोहक जलप्रपातों के लिए पूरे प्रदेश में विशेष पहचान रखता है। इन्हीं प्राकृतिक धरोहरों में शामिल है रानीदाह जलप्रपात, जो अपनी अलौकिक सुंदरता, शांत वातावरण और ऐतिहासिक लोककथाओं के कारण पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन चुका है। जशपुर नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह पर्यटन स्थल प्रकृति प्रेमियों, फोटोग्राफी के शौकीनों और रोमांच पसंद पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है।

रानीदाह तक पहुँचने का सफर भी अपने आप में यादगार अनुभव है। हरियाली से आच्छादित पहाड़ियों, घने साल के जंगलों और घुमावदार खूबसूरत सड़कों से गुजरते हुए जैसे ही पर्यटक इस स्थल पर पहुँचते हैं, सामने ऊँची चट्टानों से गिरती दूधिया जलधारा, चारों ओर फैली हरियाली और पक्षियों का मधुर कलरव मन को सुकून से भर देता है। विशेषकर वर्षा ऋतु में यह जलप्रपात अपने पूरे वैभव में दिखाई देता है, जब पानी अनेक धाराओं में विभाजित होकर ऊँचाई से नीचे गिरता है और अद्भुत प्राकृतिक दृश्य प्रस्तुत करता है।

रानीदाह केवल प्राकृतिक सौंदर्य का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि यह स्थानीय लोककथाओं और जनश्रुतियों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। प्रचलित मान्यता के अनुसार, बहुत समय पहले ओडिशा की राजकुमारी रानी शिरोमणि इन पहाड़ियों तक पहुँची थीं। जब उनके पिता और पाँच भाई उनका पीछा करते हुए यहाँ आए, तब रानी ने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इसी गहरी खाई में छलांग लगाकर अपने प्राण त्याग दिए। तभी से इस स्थान का नाम रानीदाह पड़ा, जिसका अर्थ है 'रानी का जलप्रपात'। झरने के समीप स्थित कुछ चट्टानों को आज भी स्थानीय लोग 'पाँच भैया' के नाम से जानते हैं, जिन्हें रानी के पाँच भाइयों का प्रतीक माना जाता है। यह लोककथा आज भी क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

रानीदाह जलप्रपात अपने शांत वातावरण, स्वच्छ प्राकृतिक परिवेश और मनोहारी दृश्यों के कारण परिवारों, युवाओं और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श पिकनिक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले पर्यटक प्रकृति के बीच सुकून के पल बिताने के साथ-साथ यादगार फोटोग्राफी और ट्रैकिंग का भी आनंद लेते हैं। सप्ताहांत और वर्षा ऋतु में यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक एवं धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जशपुर जिले के रानीदाह जैसे प्राकृतिक पर्यटन स्थल प्रदेश की पर्यटन पहचान को नई ऊँचाइयाँ दे रहे हैं। यदि आप प्रकृति की अनुपम छटा, शांत वातावरण और लोक संस्कृति का अनूठा अनुभव एक साथ लेना चाहते हैं, तो जशपुर का रानीदाह जलप्रपात निश्चित रूप से आपकी यात्रा सूची में शामिल होना चाहिए।

लेखक सहायक संचालक जनसंपर्क, सहायक संचालक जनसंपर्क

टिप्पणी

एल नीन्यो का उभार

इस बार मॉनसून कमजोर रहने की आशंका है। इस चुनौती के मद्देनजर सरकार ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं, इस बारे में उसे देश को भरोसे में लेना चाहिए, ताकि लोग घबराहट से बच सकें।

मौसम को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं। आधा जून गुजर चुका है और अटके मॉनसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक मानसूनी बारिश में अब तक 35 प्रतिशत की कमी दर्ज हो चुकी है। वैसे इस समय तक ऐसा होना असामान्य नहीं है, मगर चिंता बढ़ाने वाला पहलू एन नीन्यो परिघटना का सक्रिय हो जाना है। अमेरिका के राष्ट्रीय महासागरीय एवं वातावरणीय प्रशासन (एनओएए) ने 11 जून को एलान कर दिया कि भू-मध्यरेखा के पास प्रशांत महासागर में एल नीन्यो का उभार हो चुका है।

एल नीन्यो प्रशांत महासागर में होने वाले उस बदलाव को कहते हैं, जिससे समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। इसका दुनिया भर के मौसम पर असर पड़ता है और भारत में अक्सर सूखा या कम बारिश होती है। 1951 के बाद से 17 बार एन नीन्यो का उभार हुआ है, उनमें से 12 बार भारत में सामान्य से कम बारिश हुई है। एनओएए ने 1951 के बाद 17 में छह एन नीन्यो को 'अति शक्तिशालीÓ श्रेणी में रखा है। उसने कहा है कि इस बार का एन नीन्यो के भी 'अति शक्तिशालीÓ होने की संभावना है। भारत में धान, दलहन, और सब्जियों की खेती मानसूनी बारिश पर काफी हद तक निर्भर रहती है। कम बारिश होने पर डेयरी क्षेत्र भी प्रभावित होता है। इसके अलावा भू-जल के स्वस्थ स्तर के लिए भी पर्याप्त बारिश अनिवार्य है।

कम बारिश होने का पनबिजली परियोजनाओं पर भी खराब असर होता है। इसलिए बन रही स्थिति को लेकर एहतियाती कदम उठाने की अवश्यकता है। भारत के मौसम विभाग ने सामान्य की तुलना में 90 फीसदी तक ही बारिश होने का अनुमान लगाया है। लेकिन संभव है कि यह उससे भी कम हो। और ये चुनौती उस समय आई है, जब ईरान युद्ध के कारण उर्वरकों के अभाव और महंगाई की समस्या पहले से मंडरा रही है। इसलिए ये सवाल अहम है कि इन चनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने क्या एहतियातन कदम उठाए हैं? इस बारे में उसे देश को भरोसे में लेना चाहिए, ताकि लोग घबराहट से बच सकें।

ब्लॉग

शिक्षा के 'अदृश्य कर' का भारतीय परिवारों की जेब पर डाका

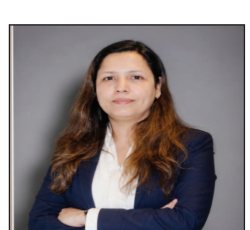

निशा सिंह

बिहार के एक गाँव का साधारण मिस्त्री परिवार अपने बेटे की सरकारी स्कूल की पढ़ाई का खर्च उठाने के बाद स्थानीय ट्यूटर को भी कुछ सौ रुपये और देता है। इसे दूसरी तरह से कहें तो बच्चे के लिए स्कूल तो मुफ्त है, लेकिन पढ़ाई नहीं, तभी तो पढ़ने के लिए ट्यूटर की जरूरत पड़ती है।

ग्रामीण भारत में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे की स्कूली शिक्षा पर परिवार सालाना लगभग 9,500 रुपये खर्च करता है। हैरानी की बात यह है कि उसी बच्चे पर उन्हीं विषयों और उसी शैक्षणिक वर्ष के लिए लगभग 7,300 रुपये अलग से निजी ट्यूशन पर खर्च हो जाते हैं। शहरों में परिवार स्कूली शिक्षा पर इससे लगभग तीन गुना अधिक खर्च करते हैं और उस खर्च का लगभग आधा हिस्सा निजी कोचिंग और ट्यूशन पर चला जाता है।

इसे 'सपनों का कर' या 'शिक्षा का अदृश्य कर' कोई भी नाम दिया जा सकता है। यह कोई ऐसा कर नहीं है जिसे सरकार ने लगाया हो या जिसे कोई विभाग वसूलता हो। फिर भी भारत का लगभग हर परिवार इसे हर महीने चुपचाप चुका रहा है। यह केवल कोचिंग उद्योग की कहानी नहीं है। यह उस भरोसे की कहानी है, जो धीरे-धीरे हमारे स्कूलों से उठता जा रहा है। आज परिवार अतिरिक्त बढ़त पाने के लिए नहीं, बल्कि इस डर से पैसा खर्च कर रहे हैं कि केवल स्कूल की पढ़ाई उनके बच्चों के भविष्य के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

अब आँकड़े इतने बड़े हो चुके हैं कि उन्हें नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) के वर्ष 2025 के आँकड़ों के अनुसार, एक स्कूली बच्चे पर परिवार औसतन 22,024 रुपये प्रतिवर्ष खर्च करता है, जिसमें अकेले निजी कोचिंग की हिस्सेदारी 40.7 प्रतिशत है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवार सबसे अधिक बोझ उठाते हैं। वह अपनी कुल शैक्षिक लागत का 29 से 46 प्रतिशत तक केवल कोचिंग पर खर्च करते हैं, जबकि निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के परिवारों के लिए यह हिस्सा आठ से 20 प्रतिशत के बीच है। शिक्षा की गुणवत्ता जितनी कमजोर होती है, परिवारों को स्कूल के बाहर उतना ही अधिक खर्च करना पड़ता है।

वर्षों से कौशल विकास और रोजगार क्षमता के क्षेत्र को करीब से देखने के बाद मुझे सबसे अधिक चिंता इस प्रवृत्ति की दिशा को लेकर होती है। ग्रामीण परिवार अपनी शिक्षा संबंधी कुल लागत का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा केवल इसलिए ट्यूशन पर खर्च कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे दूसरों से पीछे न रह जाएँ। दूसरी ओर, शहरी परिवार भले ही कुल मिलाकर अधिक खर्च करते हों, लेकिन उनके शिक्षा बजट का अपेक्षाकृत छोटा हिस्सा ही कोचिंग पर जाता है। इसका अर्थ साफ है जिस परिवार की आर्थिक क्षमता सबसे कम है, उसी पर सबसे अधिक बोझ पड़ रहा है। यह किसी व्यवस्था की अनचाही कमी नहीं, बल्कि उसी व्यवस्था का परिणाम है।

चिंता की बात यह भी है कि यह सिलसिला हर साल पहले शुरू हो रहा है। कभी कोचिंग का मतलब बोर्ड परीक्षा से पहले ग्यारहवीं या बारहवीं में अतिरिक्त तैयारी माना जाता था। आज 27 प्रतिशत स्कूली बच्चे निजी कोचिंग ले रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या ऐसे बच्चों की है जिनकी उम्र अभी प्रतिस्पर्धा का अर्थ समझने की भी नहीं हुई है। पाँच वर्ष का बच्चा भी ट्यूशन की समय-सारिणी के साथ दिखाई दे, तो अब वह असामान्य नहीं माना जाता।

यह प्रवृत्ति अचानक नहीं बनी है। दशकों से उपलब्ध एनएसएसओ के उपभोग संबंधी आँकड़े बताते हैं कि कम आय वाले परिवार अपनी आय का लगातार बढ़ता हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, जबकि अधिक आय वाले परिवार कुल राशि के लिहाज से अब भी उनसे कहीं अधिक खर्च करते हैं। भारत ने संविधान में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वादा किया था, लेकिन व्यवहार में हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है जहाँ 'मुफ्त शिक्षा' बच्चे को केवल आधी दूरी तक ले जाती है। बाकी दूरी निजी ट्यूटर पूरी करता है बशर्ते परिवार उसकी कीमत चुका सके।

आज भारतीय परिवार दो बार भुगतान कर रहे हैं, पहली बार करों के रूप में, जिनसे सरकारी स्कूल चलते हैं; और दूसरी बार निजी ट्यूशन के रूप में, ताकि वही स्कूल अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। हम स्कूलों में बढ़ते नामांकन को प्रगति का प्रमाण मान लेते हैं, लेकिन शायद ही कभी यह पूछते हैं कि उस नामांकन को वास्तव में सार्थक बनाने के लिए परिवारों को अलग से कितनी कीमत चुकानी पड़ी।

इस स्थिति के लिए किसी एक स्कूल, किसी एक कोचिंग संस्थान या किसी एक अभिभावक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह उस सामूहिक स्वीकारोक्ति का परिणाम है कि अकेला स्कूल अब वह भरोसा नहीं दिला पा रहा है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है।

जब तक बेहतर संसाधनों वाले स्कूल, जवाबदेह शिक्षण व्यवस्था और बच्चों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार नहीं होंगे, तब तक यह 'सपनों का कर' या 'शिक्षा का अदृश्य कर' भारतीय परिवारों की जेब पर हर महीने दस्तक देता रहेगा। भारत 'सपनों 'के संकट से नहीं, बल्कि भरोसे के संकट से जूझ रहा है। जब तक कक्षाओं में वह भरोसा वापस नहीं लौटता, तब तक लाखों परिवार उस शिक्षा के लिए दो बार भुगतान करते रहेंगे, जिसके लिए उन्हें केवल एक बार भुगतान करना चाहिए था।

(लेखिका कौशल विकास, रोजगार क्षमता और कार्यबल विकास के क्षेत्र में कार्यरत नीति विश्लेषक हैं। लेख में व्यक्त विचार उनके निजी हैं।)

MLA बृजभूषण राजपूत की बची जान

एस्कॉर्ट वाहन को ट्रक ने रौंदा, गनर समेत 3 घायल, पिता बोले- हत्या की साजिश

आर्यावर्त संवाददाता

महोबा। महोबा जिले में चरखारी विधायक बृजभूषण राजपूत एक सड़क हादसे में बाल-बाल बच गए। महोबा के संकट मोचन मंदिर खरेला के पास बुधवार की रात तेज रफ्तार ट्रक ने उनके एस्कॉर्ट वाहन को टक्कर मार दी। इससे विधायक के सरकारी गनर, प्राइवेट गार्ड और ड्राइवर घायल हो गए।

उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में पहुंचाया गया। विधायक के पिता व पूर्व सांसद गंगाचरण राजपूत ने हत्या की साजिश बताया। बताया जा रहा है कि भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। उनकी कार आगे चल रही थी।

विधायक की गाड़ी सुरक्षित बच गई

उनके पीछे सरकारी गनर और प्राइवेट गार्ड्स का स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट वाहन था। संकट मोचन मंदिर के केला लदे ट्रक को अपनी ओर आता देख विधायक की कार के ड्राइवर रविकांत मिश्रा ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार को सड़क से नीचे उतार दिया। इससे विधायक की गाड़ी सुरक्षित बच गई।

स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई

हालांकि, अनियंत्रित ट्रक ने विधायक की कार के पीछे आ रही स्कॉर्पियो एस्कॉर्ट गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। दुर्घटना में सरकारी गनर श्याम सिंह, प्राइवेट गार्ड किशनपाल और ड्राइवर जितेंद्र चोटिल हुए हैं। उन्हें तत्काल इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

वीबी रामजी से सुधरेगी गांवों की दशा: डिप्टी सीएम

मजदूरों के भुगतान में नहीं होगी देरी

आर्यावर्त संवाददाता

प्रयागराज। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है की 10 लाख करोड़ से अधिक खर्च करने के बाद भी मनरेगा से गांवों की दशा में सुधार नहीं हुआ है। वीबी रामजी के माध्यम से गांवों का सर्वांगीण विकास होगा। तालाब भी बनेगा और पर्यावरण संरक्षण का कार्य भी होगा। मनरेगा में 100 दिन रोजगार मिलता था लेकिन अब 125 दिन मिलेगा। 252 रुपया से बढ़ाकर 300 रुपया मजदूरी कर दी गई है।

मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में गुरुवार को आयोजित 'विकसित भारत ग्राम योजना' के राष्ट्रीय स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार का उद्देश्य गांवों को शहरों जैसी मूलभूत सुविधाओं से लैस करना और प्रत्येक पात्र परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीण विकास की योजनाओं को एकीकृत तरीके से लागू किया जा रहा है, जिससे किसी भी जरूरतमंद को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश को पहली किस्त में करीब 6.18 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं। जिन लाभार्थियों के पास भूमि नहीं है, उन्हें पट्टा उपलब्ध कराकर आवास निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवास मिलने के साथ ही लाभार्थियों को शौचालय, बिजली, पेयजल, आयुष्मान भारत योजना सहित अन्य पात्र सरकारी सुविधाओं से भी जोड़ा जाएगा। इसके लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन और समयबद्ध आवास निर्माण में देश में अग्रणी है। मनरेगा के तहत रोजगार सेवकों के भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने के लिए प्रशासनिक मद 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत किया गया है। साथ ही फर्जी जॉब कार्ड बनाकर धन निकासी पर रोक लगाने और मजदूरों को समय पर पूरा पारिश्रमिक उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था लागू की जा रही है।

केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मनरेगा के श्रमिकों का कौशल विकास कर उन्हें राजमिस्त्री एवं अन्य तकनीकी कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सके। उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार उन्हें स्वरोजगार और उद्यमिता से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बिना गारंटी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे ग्रामीण युवा और महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर सकें।

उन्होंने कहा कि अमृत सरोवर, सिंचाई सुविधाओं, ग्रामीण आधारभूत ढांचे और एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश में विकास को नई गति मिल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी गरीब परिवार कच्चे मकान में न रहे।

नोएडा के चाइल्ड पीजीआई में बड़ा हादसा टला, वार्ड में बेड पर गिरी फॉल सीलिंग, बाल-बाल बचा मासूम

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा के सेक्टर-30 में मौजूद चाइल्ड पीजीआई अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया। अस्पताल के एक वार्ड में मरीज के बेड के ऊपर अचानक फॉल सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिर गया। हादसे के वक्त बेड पर एक बच्चा मौजूद था, जो बाल-बाल बच गया। घटना के बाद वार्ड में अफरा-तफरी मच गई और अस्पताल की बिल्डिंग की गुणवत्ता तथा मरीजों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

जानकारी के मुताबिक, वार्ड में भर्ती बच्चों के बेड के ऊपर अचानक फॉल सीलिंग के गिरने के दौरान गनीमत रही कि कोई बच्चा, मरीज या तीमारदार इसकी चपेट में नहीं आया। घटना के बाद अस्पताल स्टाफ और मरीजों के परिजनों में हड़कंप मच गया।

इस घटना ने एक बार फिर सरकारी अस्पतालों की इमारतों की गुणवत्ता और रख-रखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मासूम मरीजों की सुरक्षा को लेकर परिजनों ने चिंता जताई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते ऐसी कमियों को दूर नहीं किया गया, तो भविष्य में बड़ा हादसा हो सकता है।

चाइल्ड पीजीआई के निदेशक डॉ। अरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह घटना करीब एक सप्ताह पहले की है। उनके अनुसार, छत गिरने की नहीं, बल्कि फॉल सीलिंग का एक हिस्सा टूटकर गिरने की घटना हुई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हादसे में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ है।

मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं और यह पता लगाया जा रहा है कि लापरवाही किस स्तर पर हुई है। साथ ही भवन की गुणवत्ता से जुड़ी खामियों को तत्काल दूर करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।

जांच के बाद होगी आगे की कार्रवाई

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि किसी अधिकारी, एजेंसी या ठेकेदार की लापरवाही सामने आती है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अस्पताल की अन्य फॉल सीलिंग और भवन की स्थिति का भी निरीक्षण कराया जा रहा है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

तहसील सदर में मनमानी, समय के पहले ही बंद किए जा रहे खतौनी काउंटर

सुलतानपुर। सरकार के दिशा निर्देशों का सुल्तानपुर जिले के सदर तहसील में जमकर माहौल बनाया जा रहा है। सदर तहसील में संचालित खतौनी काउंटर को 2.00 बजे के पूर्व ही बंद कर दिया जाता है। जानकारों का कहना है कि 15 के बजाय 30 रुपए सुविधा शुल्क के साथ देने पर खतौनी प्रदान की जाती है। जबकि शासन की तरफ से प्रशासन ने दोपहर 2.00 बजे तक का खुलने का समय दिया। गुरुवार को लगभग दोपहर 1.30 बजे खतौनी काउंटर के मेन गेट पर ताला जड़ दिया गया। दूरदराज से आने वाले फरियादी कर्मचारियों से मिन्नतें करते रहे, लेकिन सिर्फ सुविधा शुल्क देने वालों को ही काउंटर के अंदर स्थान दिया गया। एसडीएम सदर उत्तम तिवारी का कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी।

सहारनपुर में कमरे से युवक-युवती के शव मिले, दरवाजा तोड़कर पहुंची पुलिस, प्रेम प्रसंग के एंगल पर जांच

आर्यावर्त संवाददाता

सहारनपुर। सहारनपुर के कोतवाली सदर बाजार क्षेत्र स्थित एसबीआई कॉलोनी में बुधवार देर रात एक बंद कमरे से लैब टेक्नीशियन और एक युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम और फोरेंसिक जांच के बाद ही होगी।

पुलिस के अनुसार, सूचना मिली थी कि एसबीआई कॉलोनी स्थित एक मकान का कमरा अंदर से बंद है और काफी देर तक आवाज देने के बावजूद कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। मौके पर पहुंची सदर बाजार पुलिस ने खिड़की से अंदर देखा तो संदिग्ध स्थिति दिखाई दी। इसके बाद स्थानीय लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ा गया।

कमरे के अंदर एक युवक और एक युवती मृत अवस्था में मिले। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिनंदन सिंह और पुलिस अधीक्षक नगर व्योम बिंदल भी घटनास्थल पर पहुंचे।

युवक निजी अस्पताल में था लैब टेक्नीशियन

पुलिस ने मृतकों की पहचान सैम कमनिश (40), निवासी केरल, और आस्था (23), निवासी रसूलपुर पापड़ेकी, के रूप में की है। पुलिस के अनुसार, सैम कमनिश दिल्ली रोड स्थित एक निजी अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगी पुष्टि

फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि युवक ने पहले अपनी कलाई की नस काटी और बाद में कमरे की खिड़की से आंशिक रूप से लटककर जान दे दी। वहीं युवती की मौत प्रथम दृष्टया किसी जहरीले पदार्थ के सेवन से होने की आशंका है। पुलिस ने बताया कि युवती के शरीर पर किसी बाहरी चोट के निशान नहीं मिले हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि मौत के कारणों की पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक जांच के बाद ही किया जाएगी।

पुलिस सभी पहलुओं की कर रही जांच

क्षेत्राधिकारी द्वितीय मनोज कुमार यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा दिखाई दे रहा है। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।

फिरोजाबाद के 90 साल पुराने संस्कृत महाविद्यालय में लग गया ताला, आखिरी शिक्षक भी हो गए सेवानिवृत्त

आर्यावर्त संवाददाता

फिरोजाबाद। करौली मंदिर परिसर स्थित करीब नौ दशक पुराने हनुमान संस्कृत महाविद्यालय में आखिरकार ताला लग गया। बीते मंगलवार को अंतिम शिक्षक एवं कार्यवाहक प्राचार्य भी सेवानिवृत्त हो गए। इससे महाविद्यालय में बचे हुए 20 छात्रों का भविष्य अधर में पड़ गया है। गुरुवार को यहां ताला बंद देख कर छात्र लौट गए।

भाजपा सरकार संस्कृत को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, लेकिन जिले में उल्टी गंगा बही और 1940 से संचालित संस्कृत महाविद्यालय में आखिरकार ताला लग गया। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से मंगलवार को सेवानिवृत्त शिक्षक राम प्रकाश शास्त्री ने बताया कि यहां आवासीय गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई कराई जाती थी।

यह नेपाल तक प्रसिद्ध था, इस कारण वहां के छात्र भी प्रथमा से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई करने आते थे। कोरोना काल में आवासीय पद्धति की व्यवस्था समाप्त हो गई। महाविद्यालय में प्राचार्य और शिक्षकों के कुल पांच पद स्वीकृत थे।

धीरे-धीरे सभी सेवानिवृत्त होते गए लेकिन उनके स्थान पर नए शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई। यही कारण है कि जब वह सेवानिवृत्त हो गए तो महाविद्यालय के गेट पर ताला लग गया। उन्होंने बताया कि हनुमान ट्रस्ट की जमीन पर संचालित महाविद्यालय में शुरुआती दौर में 600 छात्र प्रथमा से लेकर आचार्य तक की पढ़ाई करते थे।

राहगीरों को जान से मारने की मिल रही धमकी

चांदा, सुल्तानपुर। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत अहिरौला ग्राम सभा में आने जाने वाले राहगीरों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम सभा निवासी विमला देवी ने इसके पूर्व में कोतवाली प्रभारी से शिकायती पत्र देकर दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी इसके बावजूद दबंगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई थकी हारी महिला ने 1 जुलाई को पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि ग्राम सभा निवासी शिवनारायण, शेषनारायण, हरि नारायण, अनुभव, आशीष, आदर्श, के खिलाफ पहले भी मुकदमा दर्ज हो चुका है,आने जाने वाले लोगों को परेशान करते हैं। इसके बावजूद उक्त आरोपी आने जाने वाले राहगीरों को मारने पीटने व जान से मार डालने की धमकी देते रहते हैं। उक्त अपराधियों जिनके खिलाफ थाना चांदा में दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

अयोध्या की बच्ची को वृंदावन के कपल ने लिया था गोद, बंदरों को खाना खिलाते समय पहली मंजिल से गिरी, मौत

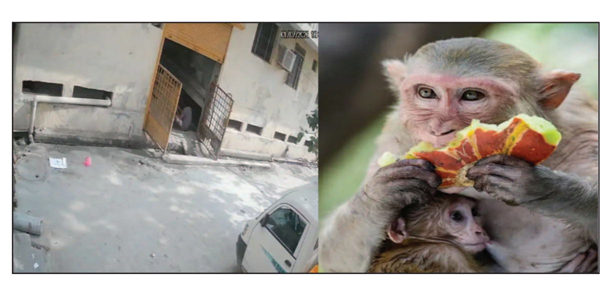

आर्यावर्त संवाददाता

मथुरा। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के वृंदावन में बंदरों के आतंक के बीच एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। संत कॉलोनी इलाके में 13 वर्षीय बच्ची बंदरों को खाना खिलाते समय पहली मंजिल की खिड़की से अचानक नीचे गिर गई। करीब 15 फीट की ऊंचाई से सड़क पर गिरने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।

हादसा वृंदावन के बांके बिहारी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित संत कॉलोनी में हुआ। मृतक बच्ची की पहचान पूर्वा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि वह मकान की पहली मंजिल पर स्थित खिड़की से बंदरों को खाना खिला रही थी। इसी दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे नीचे सड़क पर गिर गई।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्ची के गिरते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में उसका छोटा भाई मौजूद था, जबकि परिवार के अन्य सदस्य काम पर गए हुए थे।

गोद ली थी बच्ची

पूर्वा को अनिल पांडे और उनकी पत्नी ने गोद लिया था। मूल रूप से अयोध्या की रहने वाली पूर्वा पिछले कई वर्षों से उनके साथ वृंदावन में रह रही थी। अनिल पांडे अपनी पत्नी और बेटे के साथ संत कॉलोनी में किराए के मकान की पहली मंजिल पर रहते हैं। दंपति परिक्रमा मार्ग पर खाने की ठेली लगाकर परिवार का भरण-पोषण करते हैं। घटना के समय दोनों अपने काम पर गए हुए थे।

बताया जा रहा है कि वृंदावन में बंदरों की संख्या काफी अधिक है और स्थानीय लोग अक्सर उन्हें खाने-पीने की चीजें खिलाते हैं। कई बार बंदरों के अचानक झपट्टा मारने या पास आने से लोग घबरा जाते हैं, जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, बच्ची भी बंदरों को खाना खिला रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया और यह दर्दनाक हादसा हो गया।

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसमें हादसे का पूरा घटनाक्रम रिकॉर्ड हुआ है। फुटेज के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वृंदावन में बंदरों की बढ़ती संख्या लंबे समय से चिंता का विषय बनी हुई है।

नोएडा में चलते-चलते बंद हो रहे ई-रिक्शे, मोबाइल से हैक हो रहा बैटरी सिस्टम... ड्राइवरों ने बताई आपबीती

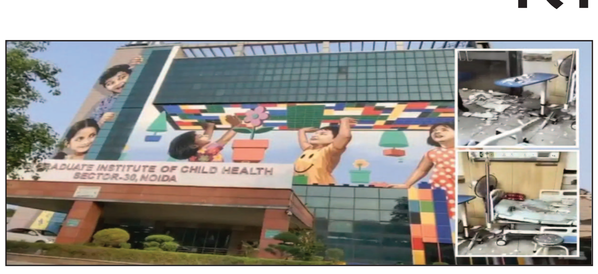

आर्यावर्त संवाददाता

नोएडा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में ई-रिक्शा चलाने वाले हजारों ड्राइवरों के बीच इन दिनों एक नई चिंता चर्चा का विषय बनी हुई है। कई ई-रिक्शा ड्राइवरों का दावा है कि उनके वाहन बिना किसी तकनीकी खराबी के अचानक चलते-चलते बंद हो जाते हैं। उनका आरोप है कि कुछ शरारती तत्व मोबाइल फोन के जरिए ई-रिक्शा के बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) से छेड़छाड़ कर बैटरी को स्विच ऑफ कर देते हैं।

ई-रिक्शा ड्राइवरों का कहना है कि कई बार वाहन पूरी तरह ठीक होने के बावजूद अचानक सड़क पर रुक जाता है। बैटरी, मोटर और अन्य तकनीकी हिस्सों की जांच कराने पर भी कोई खराबी सामने नहीं आती। इससे ड्राइवरों को घंटों सड़क पर परेशान होना पड़ता है। कई बार यात्रियों को बीच रास्ते में ही उतरना पड़ता है, जिससे ड्राइवरों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ता है।

ड्राइवरों के मुताबिक, इस तरह की घटनाएं गौतमबुद्ध नगर जिले के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही हैं। उनका कहना है कि यदि यह सिलसिला जारी रहा तो हजारों ई-रिक्शा ड्राइवरों की आजीविका प्रभावित हो सकती है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ सकता है।

> **निर्माता कंपनियों और प्रशासन से मांग**
>
> ई-रिक्शा ड्राइवरों ने प्रशासन और निर्माता कंपनियों से मांग की है कि बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम को अधिक सुरक्षित बनाया जाए। उनका सुझाव है कि हर ई-रिक्शा में पासवर्ड या मल्टी-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम अनिवार्य किया जाए, ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति वाहन के कंट्रोल सिस्टम तक पहुंच न बना सके। शोरूम संचालक सेवक शर्मा का कहना है कि पुराने मॉडल के ई-रिक्शा में इस तरह की समस्या अधिक देखने को मिल सकती है। उनके अनुसार, नए मॉडल के अधिकांश ई-रिक्शा में पहले से ही पासवर्ड आधारित सुरक्षा दी जा रही है, जिससे अनधिकृत व्यक्ति सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

मोबाइल ऐप और ब्लूटूथ से छेड़छाड़ की आशंका

ई-रिक्शा से जुड़े तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ आधुनिक ई-रिक्शा में बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) या कंट्रोलर को ब्लूटूथ या मोबाइल ऐप के जरिए मॉनिटर और नियंत्रित करने की सुविधा होती है। यदि इस सिस्टम की सुरक्षा पर्याप्त मजबूत न हो या किसी बाहरी व्यक्ति को एक्सेस मिल जाए, तो उसके साथ छेड़छाड़ की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ मामलों में 'BAT-BMS' नामक मोबाइल ऐप का भी जिक्र सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि यदि कोई व्यक्ति ई-रिक्शा के सिस्टम से कनेक्ट हो जाए तो वह बैटरी को रिमोट तरीके से स्विच ऑफ कर सकता है।

ड्राइवरों ने सुनाई अपनी परेशानी

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ई-रिक्शा चलाने वाले रादिल खान ने बताया कि दोपहर करीब 12 बजे उनका ई-रिक्शा अचानक बंद हो गया। काफी प्रयास करने के बावजूद वाहन चालू नहीं हुआ। बाद में जब वह उसे एजेंसी लेकर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि बैटरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्विच ऑफ हो गई थी, जिसे दोबारा सक्रिय किया गया।

एक अन्य चालक राहुल कुमार ने बताया कि वह सूरजपुर से नोएडा के भंगेल की ओर जा रहे थे। हल्द्वानी मोड़ के पास उनका ई-रिक्शा अचानक बंद हो गया। यात्रियों को बीच रास्ते में उतरना पड़ा और उन्हें कई घंटे तक परेशानी झेलनी पड़ी। बाद में एक मैकेनिक ने सॉफ्टवेयर के जरिए बैटरी को दोबारा ऑन किया।

ई-रिक्शा चालक चरण सिंह ने भी इसी तरह का अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि करीब 15 दिन पहले उनका वाहन चलते-चलते बंद हो गया था। शुरुआत में उन्हें बैटरी खराब होने की जानकारी दी गई, लेकिन सर्विस सेंटर में जांच के दौरान पता चला कि सॉफ्टवेयर सेटिंग में बदलाव हुआ था।

पुलिस ने क्या कहा?

एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि अभी तक इस प्रकार की किसी घटना की आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। यदि कोई शिकायत मिलती है तो उसकी तकनीकी जांच कराई जाएगी और यदि किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर वाहन के सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की पुष्टि होती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि ई-रिक्शा मालिकों को केवल अधिकृत सर्विस सेंटर से ही सॉफ्टवेयर अपडेट कराना चाहिए और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसी सुविधाओं का उपयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। वहीं, ड्राइवरों को सलाह दी जा रही है कि यदि उनके वाहन में इस तरह की समस्या आती है तो उसकी सूचना संबंधित कंपनी और पुलिस को अवश्य दें, ताकि मामले की तथ्यात्मक जांच की जा सके।

शराब की दुकान खुलने पर महिलाओं का विरोध

जौनपुर। मछलीशहर कोतवाली अंतर्गत जमुहर बाजार का है जहां पर काफी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने शराब की दुकान खुलने पर प्रदर्शन और विरोध करना चालू कर दिया । यह देशी शराब और ठंडी वियर की दुकान काफी पुरानी है और हाईवे एनएच 731 ठ जमुहर बाजार चैराहे पर स्थित है । महिलाओं का कहना है कि यहां पर हम सब का घर मकान है बच्चे रहते हैं बहू बेटियां रहती हैं और यहां पर शराब पीकर के लोग गंदी-गंदी गालियां देते हैं इसलिए हम सभी का कहना है कि यहां पर शराब की दुकान नही खुलेगी।और यहाँ से दुकान हटवाने की मांग कर रही है। महिलाओं का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था कि इतने में पुलिस पहुंची और लाठी भांजना शुरू कर दिया लेकिन महिलाएं अपने जिद पर अड़ी रही फिर ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि हम दुकान नहीं खोलेंगे तब जाकर महिलाएं शांत हुई। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए थानाध्यक्ष मछलीशहर पुलिस बल के साथ मौजूद रहे ।

कैसे जॉब ही छीन रही माता-पिता बनने का सुख!

पकी नौकरी, अप्रेजल और ऐसे बिजी रूटीन का कल्चर लोगों में एक बड़े खतरे को बढ़ा रहा है। क्या आप जानते हैं कि जॉब करने वालों में अधिकतर इनफर्टिलिटी का शिकार बन रहे हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इसकी वजह बताने जा रहे हैं और एक्सपर्ट से जानें कैसे बचाव किया जा सकता है।

भारत में महिलाओं का फर्टिलिटी आज घटकर 1.9 हो गया है। ये आंकड़ा एनएफएचएस-6 रिपोर्ट में सामने आया है। देखा जाए तो एवरेज फर्टिलिटी 2 से ऊपर होना चाहिए जबकि देश में ये लगातार घट रहा है। इनर्फिटिलिटी के पीछे कई कारण हो सकते हैं जिनमें से एक जॉब कल्चर भी है। महिलाएं और पुरुष अपने काम के स्ट्रेस में इस कदर बिजी हैं कि उनकी नौकरी ही माता-पिता बनने का सुख छीन रही है।

कई रिसर्च में पाया गया है कि नौकरी का तनाव लोगों की इनफर्टिलिटी से संबंधित समस्याओं से जुड़ा होता है। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे जॉब और बिजी लाइफ का ये रूटीन लोगों को इनफर्टिलिटी का शिकार बना रहा है।

फर्टिलिटी का क्या मतलब है

आयुर्वेदिक डॉक्टर चंचल शर्मा कहती हैं कि फर्टिलिटी किसी व्यक्ति की नेचुरली बच्चा पैदा करने की क्षमता को कहते है। यह सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही नाजुक विषय भी है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आपका कॉर्पोरेट रूटीन आपकी फर्टिलिटी में रुकावट डाल सकता है।

कॉर्पोरेट कल्चर कैसे बढ़ा रहा इनफर्टिलिटी का डर

डेस्क पोटैटो- क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि काम के घंटों के बीच आप कितनी देर तक अपनी डेस्क पर बैठते हैं? लोग सोचते है की काम करने के लिए ध्यान और निरंतरता ज़रूरी है इसलिए ज्यादा देर तक बैठना आम माना जाता है। हालांकि, यह लगातार बैठने का जाल आपकी ताकत खा रहा है, जिससे आपकी मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं। यह तब होता है जब आप अचानक मसल्स की मूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। इससे न सिर्फ़ पीठ दर्द होता है, बल्कि आपके पेल्विक एरिया में ब्लड सर्कुलेशन भी काफी धीमा हो जाता है, जिससे आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ता है।

मेलाटोनिन ट्रैप

हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी स्क्रीन से निकलने वाली नीली किरणें सिर्फ हमारी नींद में रुकावट डालती हैं। लेकिन असल में वो नीली किरणें शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन के उत्पत्ति को रोक सकती हैं। मेलाटोनिन न सिर्फ बेहतर नींद लेने में मदद करता है बल्कि यह एक असरदार एंटीऑक्सीडेंट भी है जो महिलाओं के एग्स को किसी भी तरह के नुकसान से बचाता है।

कॉफी कल्चर

कई रिसर्च से पता चला है कि जो गर्भवती महिलाएं रोजाना तीन कप से ज्यादा कॉफी पीती हैं उनमें कंसीव करने की क्षमता कम होने का डर बना रहता है या फिर ये 50% तक कम हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैफीन फैलोपियन ट्यूब में होने वाली नेचुरल एक्टिविटीज को रोकता है, जिससे सफल गर्भाधान और नेचुरल प्रेगनेंसी की संभावना में रुकावट आती है।

बढ़ती उम्र और देर से फैसले लेना

आज के व्यस्त काम-काज के माहौल ने युवा पीढ़ी के बीच फैमिली प्लानिंग के फैसले में रुकावट डाली है। इसका नतीजा यह हुआ है कि फैमिली प्लानिंग देर से होती है, जिससे उम्र की कमी के कारण महिलाओं की फर्टिलिटी पर असर पड़ता है। जन्म के समय, महिलाओं के एग्स की क्वांटिटी तय होती है। जब कोई महिला 30 साल या उससे ज़्यादा उम्र की हो जाती है तो एग्स की संख्या कम होने लगती है, जिसे लो AMH भी कहते हैं। जब तक वह गर्भधारण के लिए तैयार होती है, तब तक उनका शरीर थक चुका होता है, इसलिए उन्हें कंसीव करने में मुश्किल हो सकती है।

स्ट्रेस साइकिल भी है कारण

डेडलाइन, लगातार मीटिंग, समय पर रिजल्ट देने के दबाव से दिमाग पर बहुत ज्यादा तनाव पढता है जिससे कोर्टिसोल निकलता है, जो स्ट्रेस से निपटने वाला मुख्य हार्मोन है। लंबे समय तक कोर्टिसोल का ज़्यादा लेवल LH और FSH के निर्माण में रुकावट डालता है, जिससे कुछ महिलाओं के ओव्यूलेशन साइकिल पर भी असर पड़ता है। आसान शब्दों में कहें तो, तनाव के समय फ़र्टिलिटी का महत्व ख़तम हो जाता है। यही वजह है कि नौकरी के स्ट्रेस की वजह से कई महिलाओं को हार्मोनल इम्बैलेंस या असंतुलित पीरियड्स का अनुभव होता है।

केमिकल्स और टॉक्सिन्स के संपर्क में आना

अगर आप मैन्युफैक्चरिंग, केमिकल या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आप भी उनके साइड इफ़ेक्ट्स के संपर्क में आ सकते हैं। आपके आस-पास छिपे हुए बैक्टीरिया, जिन पर किसी का ध्यान नहीं जाता। ये केमिकल आपके हॉर्मोन में दखल दे सकते हैं, जिससे आपकी फर्टिलिटी पर असर पड़ सकता है।

एक्सपर्ट ने क्या कहा का सुझाव

एक्सपर्ट चंचल शर्मा कहती हैं कि सावधानी बरतने और प्रोटेक्टिव गियर पहनने से इनफर्टिलिटी का रिस्क कम हो सकता है। इसलिए लोगों में जॉब का स्ट्रेस कम करने के लिए ज़रूरी उपाय ढूंढ़ना तथा उन्हें लागू करना बेहद ज़रूरी है।

रसोई के लिए दोबारा लोकप्रिय हो रहे हैं लकड़ी के उपकरण

लकड़ी के रसोई उपकरण लंबे समय से हमारे घरों का हिस्सा रहे हैं। हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील जैसी नई सामग्रियों ने बाजार में जगह बना ली। अब एक बार फिर से लकड़ी के उपकरणों की मांग बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे पर्यावरण के प्रति जागरूकता और सेहत से जुड़ी चिंताएं। आइए जानते हैं कि लकड़ी के रसोई उपकरण क्यों और कैसे फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं।

पर्यावरण के अनुकूल विकल्प

आजकल लोग पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए हैं और वे ऐसे उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो पर्यावरण के अनुकूल हों। लकड़ी के रसोई उपकरण पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, क्योंकि ये नवीकरणीय संसाधनों से बनते हैं और इनका कचरा कम होता है। इसके विपरीत प्लास्टिक और स्टेनलेस स्टील के उपकरण पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होते हैं और इनका कचरा लंबे समय तक धरती पर बना रहता है।

सेहत के लिए सुरक्षित

लकड़ी के रसोई उपकरण सेहत के लिए भी सुरक्षित माने जाते हैं। प्लास्टिक उपकरणों में अक्सर हानिकारक रसायन होते हैं, जो खाने-पीने की चीजों में मिल सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के उपकरणों में भी कभी-कभी धातु के कण मिल सकते हैं, जो सेहत के लिए खराब हो सकते हैं। लकड़ी के उपकरण प्राकृतिक होते हैं और इनमें किसी प्रकार के रसायन का उपयोग नहीं किया जाता, जिससे ये सेहत के लिए सुरक्षित होते हैं।

टिकाऊ और मजबूत

लकड़ी के रसोई उपकरण टिकाऊ और मजबूत होते हैं। सही देखभाल करने पर ये कई वर्षों तक चलते रहते हैं। लकड़ी की बनावट इसे मजबूत बनाती है, जिससे ये टूटते-फूटते नहीं हैं। इनके रखरखाव में भी कोई खास परेशानी नहीं होती। इन्हें साबुन और पानी से साफ किया जा सकता है और समय-समय पर तेल लगाने से इनकी चमक बनी रहती है। लकड़ी के उपकरणों की मजबूती और टिकाऊपन इन्हें एक बेहतरीन विकल्प बनाती है।

पारंपरिक अहसास

लकड़ी के रसोई उपकरण पारंपरिक एहसास प्रदान करते हैं, जो कई लोगों को पसंद आता है। इनकी बनावट और डिजाइन साधारण होते हुए भी आकर्षक लगते हैं। ये आपके रसोईघर को एक गर्माहट और आरामदायक अहसास देते हैं। इसके अलावा लकड़ी के उपकरणों का उपयोग करने से खाना बनाते समय हाथों पर अच्छा अनुभव होता है। लकड़ी की गर्मी और स्थिरता खाना बनाने की प्रक्रिया को सुखद बनाती है।

अलग-अलग प्रकार में उपलब्ध

आजकल बाजार में कई प्रकार के लकड़ी के रसोई उपकरण उपलब्ध हैं, जिनमें चमच, चाकू और कटोरे आदि शामिल हैं। आप अपनी जरूरत के अनुसार इनकी खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इन्हें अपनी पसंद के अनुसार डिजाइन करवाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार लकड़ी के रसोई उपकरण न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं, बल्कि सेहत के लिए भी सुरक्षित होते हैं। इनकी मजबूती और पारंपरिक एहसास इन्हें एक बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

हील वाले फ्लिप-फ्लॉप्स कर रहे हैं ट्रेंड, इनके साथ आप पहन सकती हैं ये 5 आउटफिट

हील फ्लिप-फ्लॉप्स एक आरामदायक और स्टाइलिश फुटवियर विकल्प है। ये न केवल रोजमर्रा की जिंदगी में, बल्कि खास मौकों पर भी आपके लुक को खास बना सकते हैं। सही कपड़ों के साथ इन्हें पहनने से आप हर मौके पर आकर्षक दिख सकती हैं। आज के फैशन टिप्स में हम आपको बताएंगे कि किन कपड़ों के साथ हील फ्लिप-फ्लॉप्स पहनने से आपका लुक और भी बेहतरीन लगेगा।

जींस और टॉप

जींस और टॉप का मेल हमेशा से ही फैशनेबल रहा है। अगर आप हील फ्लिप-फ्लॉप्स पहन रही हैं तो डेनिम जींस के साथ एक साधारण या प्रिंटेड टॉप चुनें। यह मेल न केवल आपको आरामदायक महसूस कराएगा, बल्कि स्टाइलिश भी दिखाएगा। आप चाहें तो जैकेट या श्रग भी जोड़ सकती हैं, जिससे आपका लुक और भी खास लगेगा। इस तरह का पहनावा ऑफिस, कॉलेज या दोस्तों के साथ घूमने के लिए बेहतरीन है।

मैक्सी ड्रेस

मैक्सी ड्रेस के साथ हील फ्लिप-फ्लॉप्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह मेल आपको लंबा और पतला दिखाएगा, साथ ही आरामदायक भी रहेगा। मैक्सी ड्रेस में लंबी डिजाइन चुनें, जो आपके शरीर को खूबसूरती से दिखाएगी। इसके साथ हल्के गहने और एक छोटा-सा बैग जोड़ें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। यह पहनावा किसी भी खास मौके पर आपको आकर्षक और स्टाइलिश दिखाएगा। इन दिनों स्लिप मैक्सी ड्रेस काफी लोकप्रिय हैं।

शॉर्ट ड्रेस

शॉर्ट ड्रेस हमेशा से ही युवा और ताजगी भरा एहसास देती आई हैं। अगर आप किसी पार्टी या खास मौके पर जा रही हैं तो शॉर्ट ड्रेस के साथ हील फ्लिप-फ्लॉप्स पहन सकती हैं। यह मेल न केवल आपको आकर्षक दिखाएगा, बल्कि आरामदायक भी रहेगा। इसके साथ हल्के गहने और एक छोटा-सा बैग जोड़ें, ताकि आपका लुक पूरा हो सके। आप अपनी पसंद की डिजाइन वाली शॉर्ट ड्रेस पहन सकती हैं।

स्कर्ट और ब्लाउज

पार्टी या खास मौकों पर स्कर्ट और ब्लाउज का मेल बहुत अच्छा लगता है। रेशम या साटन की स्कर्ट के साथ एक फिटेड ब्लाउज चुनें, जो आपके शरीर को खूबसूरती से दिखाएगा। इसके साथ हील फ्लिप-फ्लॉप्स पहनें, ताकि आपका लुक और भी खास लगे। इस तरह का पहनावा किसी भी खास मौके पर आपको आकर्षक और स्टाइलिश दिखाएगा। आप चाहें तो हल्के गहने और एक छोटा-सा बैग भी जोड़ सकती हैं।

पारंपरिक सूट

अगर आप पारंपरिक लुक पसंद करती हैं तो अनारकली सूट या सलवार-कमीज के साथ हील फ्लिप-फ्लॉप्स पहन सकती हैं। यह मेल आपको पारंपरिक और आधुनिक, दोनों ही अंदाज में दिखाएगा। पारंपरिक सूट में लंबी डिजाइन चुनें, जो आपके शरीर को खूबसूरती से दिखाएगा। इसके साथ हल्के गहने और एक छोटा-सा बैग जोड़ें ताकि आपका लुक पूरा हो सके। इस तरह का पहनावा किसी भी खास मौके पर आपको आकर्षक और स्टाइलिश दिखाएगा।

सुकन्या से लेकर पीपीएफ तक...छोटी बचत योजनाओं के ब्याज में नहीं हुआ कोई बदलाव

केंद्र सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने वालों के लिए अहम जानकारी दी है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही (1 जुलाई से 30 सितंबर) के लिए ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों को अपनी जमा पूंजी पर पहली तिमाही के बराबर ही तय और सुरक्षित रिटर्न मिलता रहेगा।

9

सरकार ने छोटी बचत योजनाओं में अपनी गाढ़ी कमाई लगाने वाले आम लोगों के लिए नई ब्याज दरों की स्थिति साफ कर दी है। वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही, यानी 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) सहित अन्य सभी प्रमुख स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स के रिटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसका सीधा मतलब यह है कि निवेशकों को आने वाले तीन महीनों तक बिल्कुल उतना ही मुनाफा मिलता रहेगा, जितना उन्हें अप्रैल से जून वाली पहली तिमाही में मिल रहा था।

तिमाही से दरें रहीं जस की तस

छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में आखिरी बड़ा बदलाव साल 2023-24 की आखिरी तिमाही (जनवरी-मार्च) में हुआ था। इसके बाद अप्रैल 2024 में सरकार ने बस दो स्कीमों में थोड़ा बदलाव किया था—3 साल वाली टाइम डिपॉजिट की ब्याज दर 7% से बढ़ाकर 7.1% और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) की दर 8% से बढ़ाकर 8.2% कर दी गई थी। तब से लेकर अब तक, यानी पिछले 9 क्वार्टर से, बाकी सभी स्कीमों की ब्याज दरें वैसी ही बनी हुई हैं। इनमें कोई बदलाव

किस योजना पर मिल रहा कितना मुनाफा?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY): 8.2%
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS): 8.2%
नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC): 7.7%
किसान विकास पत्र (KVP): 7.5%
पोस्ट ऑफिस 5-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD): 7.5%
पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम (POMIS): 7.4%
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF): 7.1%
पोस्ट ऑफिस 3-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD): 7.1%
पोस्ट ऑफिस 2-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD): 7.0%
पोस्ट ऑफिस 1-वर्षीय टाइम डिपॉजिट (FD): 6.9%
पोस्ट ऑफिस 5-वर्षीय रेकरिंग डिपॉजिट (RD): 6.7%

नहीं हुआ है।

कैसे तय होता है आपका रिटर्न?

अक्सर यह सवाल उठता है कि इन ब्याज दरों का निर्धारण आखिर सरकार करती कैसे है। दरअसल, हर तीन महीने (तिमाही) में इन छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों की बारीकी से समीक्षा की जाती है। रिटर्न तय करते समय मुख्य रूप से सरकारी बॉन्ड यील्ड पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा, बाजार में चल रही सामान्य ब्याज दरों की दिशा, देश की घरेलू अर्थव्यवस्था की स्थिति के साथ-साथ वैश्विक आर्थिक माहौल को भी ध्यान में रखकर ही अंतिम फैसला लिया जाता है।

क्यों खास हैं ये सरकारी विकल्प?

लंबी अवधि का नजरिया रखने वाले सुरक्षित निवेश के चाहवान पारंपरिक निवेशकों के लिए ये योजनाएं आज भी सबसे बेहतरीन टूल मानी जाती हैं।

पूरी सरकारी गारंटी: ये सभी स्कीम्स पूरी तरह से सरकार समर्थित हैं। इसका सीधा अर्थ है कि इनमें लगाए गए आपके पैसे के डूबने का जोखिम शून्य होता है।

निश्चित रिटर्न का भरोसा: शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव का इन योजनाओं पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। आपका तय रिटर्न पूरी तरह से सुरक्षित रहता है।

शानदार टैक्स बचत: सुकन्या समृद्धि और पीपीएफ जैसी लोकप्रिय योजनाओं में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80C के तहत शानदार टैक्स छूट का सीधा फायदा मिलता है।

डिजिटल कृषि की बड़ी सफलता, किसान सारथी प्लेटफॉर्म से 3 करोड़ किसानों को मिल रहा लाभ

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि किसान सारथी प्लेटफॉर्म के साथ 4,767 आईसीएआर वैज्ञानिक और 113 आईसीएआर संस्थान जुड़े हुए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर अब तक 2.95 करोड़ किसान पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें 56.16 लाख महिला लाभार्थी भी शामिल हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जुलाई 2021 में शुरू किए गए इस एकीकृत डिजिटल कृषि-सलाहकार मंच पर अब तक 19.21 लाख प्रश्नों का समाधान किया जा चुका है। इसके अलावा, किसानों के लिए 351 कृषि उत्पादों से संबंधित 21,900 कृषि सलाह भी जारी की गई हैं।

करीब 2.89 करोड़ किसानों ने अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) जाकर इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कराया। इनमें से 5.35 लाख किसान कॉल सेंटर के माध्यम से, 21,517 मोबाइल एप्लिकेशन के जरिए, 2,416 वेब पोर्टल के माध्यम से और 39,193 कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए पंजीकरण हुए।

सरकार ने बताया कि किसान सारथी की सेवाएं देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, 768 जिलों और 6.63 लाख गांवों तक पहुंच चुकी हैं।

यह प्लेटफॉर्म इंटरैक्टिव इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेशन सिस्टम (आईआईडीएस) का उपयोग करता है, जिससे किसानों और कृषि विशेषज्ञों के बीच दो-तरफा संवाद संभव हो पाता है। साथ ही, कृषि अनुसंधान से जुड़ी जानकारी सीधे खेतों तक पहुंचाने में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों को समय पर, विश्वसनीय और कई भाषाओं में कृषि संबंधी सलाह उपलब्ध कराई जाती है।

इसके अलावा, किसानों को सरकारी योजनाओं की जानकारी, मौसम से जुड़े अपडेट और विशेषज्ञों से सीधे परामर्श की सुविधा भी मिलती है।

यह प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसे भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान और डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन ने विकसित और लागू किया है।

सरकार का कहना है कि इन सभी संस्थानों के एक साथ जुड़ने से देश भर में कृषि सलाह का एक मजबूत राष्ट्रीय नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे किसानों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार भरोसेमंद और उपयोगी सलाह मिल रही है।

यह प्लेटफॉर्म किसान कॉल सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मायस्कीम और भाषिनी जैसी प्रमुख राष्ट्रीय सेवाओं से भी जुड़ा हुआ है, जिसके जरिए किसानों को 610 सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है, जिनमें 102 योजनाएं केंद्र सरकार की हैं।

इस प्लेटफॉर्म पर सभी प्रमुख अनाज, दलहन, तिलहन, बागवानी फसलों, बागान फसलों और चारा फसलों से संबंधित कृषि सलाह उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा पशुपालन, पोल्ट्री, मत्स्य पालन और अन्य संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी जानकारी भी किसानों को दी जाती है। किसान अपनी स्थानीय भाषा में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं और उसी भाषा में सलाह प्राप्त कर सकते हैं।

किसान सारथी प्लेटफॉर्म 13 क्षेत्रीय भाषाओं में विशेषज्ञों से लाइव बातचीत की सुविधा भी देता है। साथ ही, किसानों के लिए एक ज्ञान भंडार भी उपलब्ध कराता है। इससे कृषि अनुसंधान संस्थानों की पहुंच बढ़ी है और वैज्ञानिक सलाह अधिक से अधिक किसानों तक पहुंच रही है।

सरकार के अनुसार, यह प्लेटफॉर्म ज्ञान साझा करने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के साथ-साथ कृषि अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग को भी बढ़ावा दे रहा है।

होर्मुज पर ईरान तो पनामा कैनाल पर चीन से अमेरिका का पंगा...

वॉशिंगटन, एजेंसी। ईरान-अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट को लेकर खींचतान चल ही रही है इस बीच एक बार फिर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कैनाल का जिक्र कर दिया है।उन्होंने कहा कि अमेरिका को इसका कंट्रोल कभी भी पनामा के हाथों में नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि पनामा ने कैनाल पर ट्रांजिट फीस बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। ट्रंप ने इस पनामा कैनाल पर चीन से भी पंगा लेते हुए कहा कि वह इस अहम जलमार्ग पर बीजिंग को कभी असर नहीं जमाने देंगे।

राष्ट्रपति बुधवार यानी 01 जुलाई को मेडोरा में थियोडोर रूज़वेल्ट प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी का उद्घाटन करने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कैनाल को पनामा को सौंपने की आलोचना करते हुए कहा कि

अमेरिका इसपर चीन द्वारा कंट्रोल करने की कोशिश का पूरी तरह से विरोध करेगा।

'पनामा ने बहुत पैसा कमाया'

ट्रंप ने कहा हमने पनामा को पनामा कैनाल सौंप दिया। उन्होंने सबसे पहले जहाजों के लिए कीमतें चार गुना बढ़ा दीं। इस दौरान उनका एक भी जहाज कम नहीं हुआ। फिर उन्होंने दो बार और कीमतें बढ़ाईं, इस दौरान भी उनका एक भी जहाज कम नहीं हुआ। पनामा ने इससे सालों-साल बहुत पैसा कमाया। यह हमारी तरफ से कितनी बड़ी बेवकूफी थी।

चीन को पनामा कैनाल पर कब्जा नहीं करने देंगे- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि चीन पनामा नहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ट्रंप ने ये बातें साल 1977 में हुई की टोरिजोस-कार्टर संधियों के बारे में थीं, जिनके तहत अमेरिका पनामा नहर का कंट्रोल सौंपने के लिए सहमत हुआ था। इसके बाद अमेरिका ने साल 1914 में बनाई नहर को 1999 में पनामा को सौंप दिया। बता दें इससे पहले भी पनामा कैनाल को लेकर अपनी नाराजगी दिखा चुके हैं।

पनामा कैनाल इतना अहम क्यों?

पनामा कैनाल को दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक रूप से सबसे अहम शिपिंग मार्गों में गिना जाता है। इस कैनाल से हर साल दुनिया का तकरीबन 5 प्रतिशत व्यापार होकर गुजरता है। इस रास्ते लगभग270 अरब डॉलर का माल ले जाया जाता । यह कैनाल अमेरिका के कंटेनर ट्रैफ़िक का लगभग 40 प्रतिशत संभालता है। बता दें पनामा कैनाल लगभग 82 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह अटलांटिक की तरफ़ कैरिबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह कोलोन से शुरू होकर गैटुन झील और गैलार्ड कट से गुजरकर पनामा सिटी तक पहुंचता है। इस कैनाल के बनने से पहले अटलांटिक और प्रशांत महासागरों के बीच यात्रा करने वाले जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के चारों ओर मैगलन जलडमरूमध्य या केप हॉर्न से होकर जाना पड़ता था। इससे यात्रा की दूरी और समय दोनों बढ़ जाते थे। इस कैनाल के बनने के बाद सेन्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी को लगभग 8,000 मील कम हो गई थी।

अरब सागर में इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान US नेवी का हेलीकॉप्टर क्रैश, एक सैनिक लापता

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी नौसेना का MH-60S सी हॉक हेलीकॉप्टर अरब सागर में इमरजेंसी वॉटर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में एक क्रू मेंबर लापता हो गया है, वहीं तीन अन्य घायल हैं। अमेरिकी नौसेना के बयान के मुताबिक, हेलीकॉप्टर 1 जुलाई को सुबह 3:30 बजे (EDT) दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये हेलीकॉप्टर USS जॉर्ज एच।डब्ल्यू। बुश (निमित्ज़-क्लास) एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनात था। नौसेना ने अपने बयान में कहा कि ये हमले की वजह से नहीं हुआ था। इसके लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है और लापता क्रू मेंबर की तलाश की जा रही है। नौसेना ने बताया कि हेलीकॉप्टर में चार क्रू मेंबर सवार थे, इनमें से तीन को घायल अवस्था में बचा लिया गया, जबकि एक अभी भी लापता है। लापता क्रू मेंबर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। नौसेना के मुताबिक, "इस इलाके में मौजूद अमेरिकी नौसेना के जहाज और दूसरे साधन अभी भी लापता क्रू सदस्यों की तलाश कर रहे हैं।" "घटना की वजह की जांच की जा रही है।" ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच, USS जॉर्ज डब्ल्यू बुश मध्य पूर्व में अमेरिकी नौसेना की तैनाती का एक अहम हिस्सा रहा है। यह अप्रैल 2026 से मध्य पूर्व इलाके में मौजूद है और इस क्षेत्र में तैनात अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर में से एक है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना का बेड़ा बहरीन में 'नेवल सपोर्ट एक्टिविटी' से ऑपरेट करता है। यह फिफ्थ फ्लीट फारस की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में सक्रिय है।

102 मंजिला बिल्डिंग के टॉप पर किया प्रपोज

न्यूयॉर्क, एजेंसी। लोग प्रपोज करने के लिए लगातार नए-नए तौर-तरीके अपनाते रहते हैं। अब एक शख्स अपनी जान जोखिम में डालकर अमेरिका की मशहूर और 102 मंजिला ऊंची एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप पर जाकर अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। हालांकि इस जोड़े का यह बेहद ही खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, लेकिन जैसे ही दोनों नीचे उतरे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

न्यूयॉर्क शहर की मशहूर इमारत, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की सबसे ऊंची चोटी पर कल बुधवार को शादी का प्रस्ताव रखने का एक अनोखा और बेहद खतरनाक मामला सामने आया। ये दोनों लोग बिल्डिंग के उस हिस्से तक चढ़ गए थे जहां आम लोगों के जाने की मनाही है।

गिरफ्तार किए गए इन दोनों लोगों की पहचान एंजेला निकोलाऊ और इवान बीरकुस के तौर पर हुई है। ये दोनों रूसी हैं और "रूफटॉपर" हैं। पहले भी दोनों खतरनाक स्टंट करते रहे हैं। इससे पहले ये चीन के तियानजिन और लॉस एंजिल्स जैसे शहरों में भी ऐसा ही स्टंट कर चुके हैं। बिल्डिंग पर चढ़ने के दौरान दोनों ने काले रंग के कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे ढके हुए लग रहे थे।

टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने गगनचुंबी इमारत की चोटी स्पायर पर एक बड़ा काला बैनर लहराया, जिस पर लिखा था- "जब प्यार की ताकत, ताकत के प्यार पर हावी होती है, तो दुनिया में शांति आती है। हालांकि यह साफ नहीं हो सका है कि वे दोनों इमारत के आखिरी हिस्से तक कैसे पहुंचने में कामयाब हो गए, जो मिडटाउन मैनहट्टन में 1,454 फीट (443 मीटर) की ऊंचाई पर स्थित है। स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस रोमांचक स्टंट पर नजर रखने के लिए घटनास्थल के पास NYPD का एक हेलीकॉप्टर और हवा में एक ड्रोन मौजूद था। दोपहर 12:30 बजे के कुछ ही देर बाद, दोनों लोग बिल्डिंग के टॉप पर लगे एंटीना वाले ढांचे के थोड़े निचले प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे। फिर एक व्यक्ति घुटने के बल बैठा और ऐसा लगा जैसे उसने महिला को शादी के लिए प्रपोज किया हो। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे को गले लगाया और किस भी किया।

हालांकि बुधवार दोपहर न्यू यॉर्क पुलिस की ओर से जारी बॉडी-कैमरा फुटेज में पुलिस को उन दोनों को पकड़ते हुए दिखाया गया। इसमें एक अफसर दोनों से कहता है, "आप यहां ऊपर नहीं आ सकते।" पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया, "बुधवार, 1 जुलाई को करीब 12 बजे, मिडटाउन साउथ प्रीसिंक्ट इलाके में 20 वेस्ट 34 स्ट्रीट पर स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के एंटीना पर 2 अनजान लोग देखे गए। न्यू यॉर्क पुलिस की इमरजेंसी सर्विसेज यूनिट ने तत्काल कार्रवाई की।" पुलिस के बयान में आगे कहा गया, "बिना किसी घटना के दोनों लोगों को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

रात में आसमान की अनोखी तस्वीरें लेगा दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा, भारतीय वैज्ञानिक भी इस मिशन का हिस्सा

वॉशिंगटन, एजेंसी। दुनिया के सबसे अहम खगोलीय प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। इसमें भारतीय वैज्ञानिक अहम भूमिका निभा रहे हैं। चिली में स्थित वेरा रुबिन ऑब्जर्वेटरी ने 10 साल तक चलने वाले लिगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम (LSST) नाम का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा रात के आसमान की बार-बार तस्वीरें लेगा। इन तस्वीरों में छोटे-छोटे एस्टेरॉयड से लेकर फटते तारे, ब्लैक होल और दूर की आकाशगंगाओं तक सब कुछ कैद होगा।

वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारा नया डेटा मिलेगा, जिससे ब्रह्मांड के कई बड़े रहस्य सुलझ सकते हैं। इसमें पुणे के IUCAA और NCRA-TIFR के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। सुरहुद मोरे, रुबिन-IUCAA प्रोग्राम मैनेजर हैं। उन्होंने कहा कि ये सर्वे खगोल विज्ञान में एक नए अध्याय की शुरुआत है। "रुबिन LSST सर्वे खगोल विज्ञान के लिए एक नए युग की शुरुआत का वादा करता है।"

भविष्य में ब्रह्मांड कैसे बदलेगा इसकी भी जानकारी

सुरहुद मोरे ने कहा, "चाहे आपकी दिलचस्पी सोलर सिस्टम के बनने को समझने में हो, फटते हुए तारों को खोजने में हो, तारों को चीर-फाड़ देने वाले ब्लैक होल का पता लगाने में हो, आधे आसमान में डार्क मैटर का नक्शा बनाने में हो, या यह समझने में हो कि भविष्य में ब्रह्मांड कैसे बदलेगा, यह सब इसमें शामिल है।" भारतीय शोधकर्ताओं का एक और बड़ा योगदान 'ग्रेविटेशनल लेंसिंग' के अध्ययन में होगा। यह अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा बताई गई एक घटना है, जिसमें विशालकाय चीजों की ग्रेविटी दूर की गैलेक्सी से आने वाली रोशनी को मोड़ देती है, जिससे एक ही चीज की कई तस्वीरें बनती हैं।

LSST स्ट्रॉन्ग लेंसिंग साइंस कोलैबोरेशन की को-चेयर अनुप्रीता मोरे ने कहा कि इस ऑब्जर्वेटरी से ऐसे 10,000 से ज्यादा ग्रेविटेशनल लेंस खोजने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, "लेंसिंग की वजह से सुपरनोवा या किलोनोवा जैसी कुछ दुर्लभ घटनाएं असामान्य रूप से ज्यादा चमकदार दिख सकती हैं, लेकिन वे एक से ज्यादा बार भी होती हुई दिख सकती हैं। इससे हमें 'देजा वू' जैसा अनुभव होता है। ऐसी ग्रेविटेशनल लेंसिंग वाली घटनाएं न केवल शानदार नजारा पेश करती हैं, बल्कि ब्रह्मांड की उम्र और उसके फैलने की दर को मापने में भी हमारी मदद करती हैं।"

भारतीय वैज्ञानिक रूबिन के डेटा का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पर गैलेक्सी का अध्ययन करने के लिए भी उत्सुक हैं। NCRA-TIFR के योगेश वाडाडेकर, जो LSST गैलेक्सीज साइंस कोलैबोरेशन का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा कि टेलीस्कोप बहुत गहरी तस्वीरें देगा जो वैज्ञानिकों को लगभग 20 अरब गैलेक्सी का अध्ययन करने में मदद करेगा, जिनमें से हर एक का अपना इतिहास अरबों साल पुराना है।

पाकिस्तान के निशाने पर अमरनाथ यात्रा, हमले की रच रहा साजिश, एजेंसियां अलर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। अमरनाथ यात्रा के बीच सुरक्षा एजेंसियों को एक अहम खुफिया इनपुट मिला है। जानकारी के मुताबिक, पाकिस्तान स्थित आतंकी हैंडलर जम्मू संभाग के अंतरराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से लगे सांबा और कठुआ सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियार और गोला-बारूद गिराने की साजिश रच रहे हैं। इस इनपुट के बाद सुरक्षा एजेंसियों और सीमा पर तैनात बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सूत्रों के अनुसार, पिछले दो-तीन दिनों के दौरान पाकिस्तान के सियालकोट जिले के बदाला गुजरां इलाके में कई पाकिस्तानी आतंकी हैंडलरों की गतिविधियां देखी गई हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं बैठकों में भारतीय सीमा में हथियार पहुंचाने की योजना बनाई गई है।

अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश

एजेंसियों को आशंका है कि अगले दो से तीन सप्ताह के भीतर सांबा और कठुआ सेक्टर में ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप गिराने की कोशिश की जा सकती है। इन हथियारों का इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकियों तक पहुंचाने और अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की साजिश के तहत किया जा सकता है।

तलाशी अभियान जोरों पर

खुफिया इनपुट के बाद सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), जम्मू-कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निगरानी और तलाशी अभियान तेज कर दिए हैं। ड्रोन रोधी तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और गश्त को भी बढ़ाया गया है ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते नाकाम किया जा सके।

संवदेनशील इलाकों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम

सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी संगठन माहौल खराब करने और दहशत फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। इसी वजह से यात्रा मार्ग, बेस कैंप और अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था पहले से और अधिक कड़ी कर दी गई है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि यह खुफिया इनपुट एहतियात के तौर पर लिया गया है और सभी संबंधित बलों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आतंकी साजिश को समय रहते विफल किया जा सके। अमरनाथ यात्रा 2026, 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त को खत्म होगी। ये यात्रा 57 दिनों तक चलेगी। ये तारीखें श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) से ली गई हैं। यात्रा आमतौर पर रक्षा बंधन के दिन खत्म होती है, जब पवित्र छड़ी, 'छड़ी मुबारक', गुफा में पहुंचती है।

मॉनसून की सुस्ती का नहीं पड़ेगा असर, सरकार ने तैयार कर लिया निपटने का प्लान

नई दिल्ली, एजेंसी। मॉनसून की धीमी गति से सरकार सतर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल यानी बुधवार को कैबिनेट बैठक में मंत्रालयों को आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए थे। मौसम विभाग के अनुसार, जून में 12 वर्षों में सबसे कम बारिश हुई। वहीं, जुलाई में भी औसत से कम बारिश की संभावना है। अब तक औसत से 43 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई है। फसलों पर भी इसके असर की आशंका जताई जा रही है।

अल नीनो के कारण मॉनसून प्रभावित हुआ है। कहीं कम तो कहीं अधिक बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल कैबिनेट की बैठक में मॉनसून को लेकर चर्चा की। दस मंत्रालयों और विभागों से सतर्क रहने को कहा गया है। कृषि, खाद्य, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, ऊर्जा, जलशक्ति, पशुपालन, डेयरी, गृह और वित्त मंत्रालय को तैयारी के निर्देश दिए गए हैं।

इन मंत्रालयों को पहले से ही सभी तैयारी करने को कहा गया है। कृषि मंत्री कह चुके हैं कि 315 जिलों में कमजोर मॉनसून से चुनौतियां हैं 111 जिलों में सिंचाई उपलब्धता 25 फीसदी से कम है। मॉनसून से प्रभावित जिलों में 12 राज्य हैं। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु शामिल है।

जलाशयों के जलस्तर पर रखी जा रही नजर

सरकार वीबी जी राम जी (ग्रामीण रोजगार मिशन) का बजट बढ़ाने पर विचार कर रही है। मौजूदा बजट 95 हजार करोड़ है और एक जुलाई से लागू इस कानून में मजदूरी दर 300 से 409 रुपए, सिक्किम में कुछ पंचायतों में 450 रुपए की विशेष दर है। कमजोर मॉनसून की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रोजगार देने की योजना बनाई गई है। जलाशयों के जलस्तर पर नजर रखी जा रही है क्योंकि इससे बिजली उत्पादन पर असर हो सकता है। वैकल्पिक स्रोतों से बिजली उत्पादन की भी तैयारी है।

अल्फा को सेंसर बोर्ड ने दी हरी झंडी, अलिया भट्ट की मूवी को मिला यूए16+ सर्टिफिकेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की फिल्म अल्फा का अच्छा खासा बज बना हुआ है। एक्शन और स्पाई फिल्म ऐल्फा का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, जिसे देखकर लोग 7 वें आसमान पर पहुंच गए। अल्फा पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिल्म में बॉबी देओल और अनिल कपूर भी अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाले हैं। इस बीच ऐल्फा को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक सेंसर बोर्ड ने ऐल्फा को हरी झंडी दे दी है।

बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट और शरवरी की आने वाली फिल्म अल्फा रिलीज से पहले ही चर्चा में है। यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने यूए 16+ सर्टिफिकेट दिया है। शिव रवैल के निर्देशन में बनी यह फिल्म 3 जुलाई को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म के टीजर और ट्रेलर में आलिया भट्ट पहली बार दमदार एक्शन अवतार में नजर आईं, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई। सीबीएफसी ने फिल्म को 2 घंटे 20 मिनट (140 मिनट) की रनटाइम के साथ मंजूरी दी है। सीबीएफसी की वेबसाइट पर फिल्म की कहानी की एक झलक भी सामने आई है। इसके मुताबिक, आलिया भट्ट का किरदार सीता बदले की आग में जलती एक ऐसी लड़की है, जो अपने रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को खत्म करने के लिए तैयार रहती है। लेकिन सफर के दौरान उसे अपनी जिंदगी से जुड़े कई बड़े राज पता चलते हैं। कहानी में सीता को निडर, सख्त और किसी भी हद तक जाने वाली लड़की के रूप में दिखाया गया है।

बताते चलें कि फिल्म ऐल्फा के टीजर और ट्रेलर को अब तक मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। अब देखना होगा कि यह फैसला कितना सफल साबित होता है। बॉक्स ऑफिस पर ऐल्फा को वेलकम टू द जंगल से कड़ी टक्कर मिलेगी, जबकि 10 जुलाई को रिलीज होने वाली धमाल 4 भी इसकी चुनौती बढ़ा सकती है।

श्वेता तिवारी ने रेड ड्रेस में बिखेरा जलवा, स्माइल से लूट लिया करार

श्वेता तिवारी सिर्फ एक एक्टिव और टैलेंटेड एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि स्टाइल आइकन भी हैं। उनके फैशन सेंस में सिंपल और एलिगेंट का परफेक्ट मिक्स नजर आता है जो हर मौके पर उनके लुक को परफेक्ट बनाता है। चाहे रैड कार्पेट हो या कैजुअल आउटिंग, श्वेता हमेशा अपनी स्टाइल और ग्रेस से लोगों को इंप्रेस करती हैं। उनके इस इंस्टाग्राम पोस्ट में भी ये साफ दिखाई देता है कि वो फैशन और परफॉर्मेंस दोनों में बराबर एक्सील करती हैं।

श्वेता तिवारी हमेशा से ही अपने स्टाइल और परफॉर्मेंस के लिए फैंस के बीच काफी पॉपुलर रही हैं। इस इंस्टाग्राम पोस्ट में उनका लुक देखते ही बनता है। श्वेता रेड कलर की लेयर्ड ड्रेस में नजर आ रही हैं जो उनके स्टाइल और ग्रेस को और निखार रही है। ड्रेस की फ्लोइंग लेयर्स उनके मूवमेंट के साथ खूबसूरती से झूल रही हैं और उनका सिंपल लेकिन एलिगेंट स्टाइल उन्हें मॉडर्न और क्लासिक दोनों तरह का लुक दे रहा है। उन्होंने अपने लुक को गोल्डन ईयररिंग्स और पेस्टल हील्स के साथ कंप्लीट किया है जो उनकी पर्सनालिटी को और हाईलाइट कर रहे हैं। उनके बाल खुले और सॉफ्ट वेव्स में सेट हैं, जो उनके चेहरे की खूबसूरती को और निखारते हैं। उनके नेचुरल पोज ने तस्वीर को और भी खास बना दिया है। वर्क फ्रंट की बात करें तो श्वेता तिवारी ने टेलीविजन इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत बेहद कम उम्र में की थी और धीरे-धीरे खुद को टॉप टीवी एक्ट्रेस बन गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा पहचान कसौटी जिंदगी की की प्रेरणा के रूप में मिली, जहां उन्होंने प्रीति का रोल निभाया। इसके अलावा श्वेता ने कई रियलिटी शो जैसे कि खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा में नजर आई थी। टीवी सीरियल्स के अलावा, उन्होंने वेब शोज और प्रिंट कमर्शियल्स में भी अपने एक्टिंग स्किल्स को दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही नेचुरल और दिल को छू लेने वाली रही है जिससे फैंस उनके हर प्रोजेक्ट में जुड़े रहते हैं।

आलिया पर हुआ समय रैना की संगत का असर, मजाक बनाने वाले को दिया मुंहतोड़ जवाब, वायरल हुआ वीडियो

'अल्फा' को रिलीज होने में चंद दिन बाकी हैं, ऐसे में आलिया भट्ट अपनी इस फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रही हैं। हालिया एक प्रमोशन में उनका अलग अंदाज देखकर फैंस दंग रह गए। जिस तरह से उन्होंने अपना मजाक बनाने वाले शख्स को जवाब दिया, उनका वो अंदाज वायरल हो गया है।

हाल ही में आलिया भट्ट राजस्थान की एक यूनिवर्सिटी में पहुंचीं। अपनी फिल्म का प्रमोशन वह कॉलेज के बच्चों के बीच कर रही थीं। इस बीच कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने उन्हें मजेदार सवाल पूछे। वहीं किसी ने बीच ही टोक दिया और अटपटा सा जवाब दिया। इस पर आलिया भट्ट ने जो जवाब दिया, वह अब वायरल हो रहा है। जानिए, ऐसा क्या जवाब आलिया भट्ट ने टोकने वाले कॉलेज स्टूडेंट को दिया। यह वीडियो देखकर कई यूजर्स का कहना है कि आलिया भट्ट पर स्टैंडअप कॉमेडी समय रैना का असर पड़ने लगा है, वह भी मुंहफट बन चुकी हैं।

आलिया भट्ट ने क्या जवाब दिया था?

वायरल वीडियो में आलिया भट्ट से एक कॉलेज स्टूडेंट ने पूछा, 'आप इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे अनफिल्टर्ड शो में हिस्सा लेने के लिए कैसे तैयार हो गईं?' आलिया इस सवाल का जवाब देतीं, इससे पहले ही एक कॉलेज स्टूडेंट ने कहा, 'पैसा।' इस आलिया ने कहा, 'किसने बोला ये, किसी गरीब आदमी ने।' इस बात सुनकर हॉल में मौजूद सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे, आलिया के जवाब पर तालियां बजाने लगे। बता दें कि यही डायलॉग स्टैंडअप कॉमेडी समय रैना ने अपने शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में कहा था। जब यह बात उन्होंने कही थी तो आलिया शो में बतौर गेस्ट मौजूद थीं।

कब रिलीज होगी आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा'?

आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' 3 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा बॉबी देओल, शरवरी और अनिल कपूर जैसे बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। 'अल्फा' यशराज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म है।

स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक प्रभात पांडेय द्वारा साई ऑफसेट प्रिंटर्स 40, वासुदेव भवन कैसरबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 2/74, विक्रांत खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित ।
शाखा कार्यालय: S-15/109, सेक्टर -15, इंदिरा नगर, लखनऊ। समस्त लेख, रचनाओं एवं विज्ञापन में लेखन और विज्ञापनदाताओं के अपने विचार हैं। इसके लिए आर्यावर्त क्रांति की कोई जिम्मेदारी नहीं है। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ, उत्तर प्रदेश ही होगा।
RNI No: UPHIN/2014/57034
Website: aryavartkranti.com
*सम्पादक: प्रभात पांडेय
सम्पर्क: 9839909595, 8765295384
Email: aryavartkrantidainik@gmail.com